वर्ष-10, अंक-7, अप्रैल-2025

मूल्य: ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

WAQF BOARD

अराजकता में डूबा बंगाल

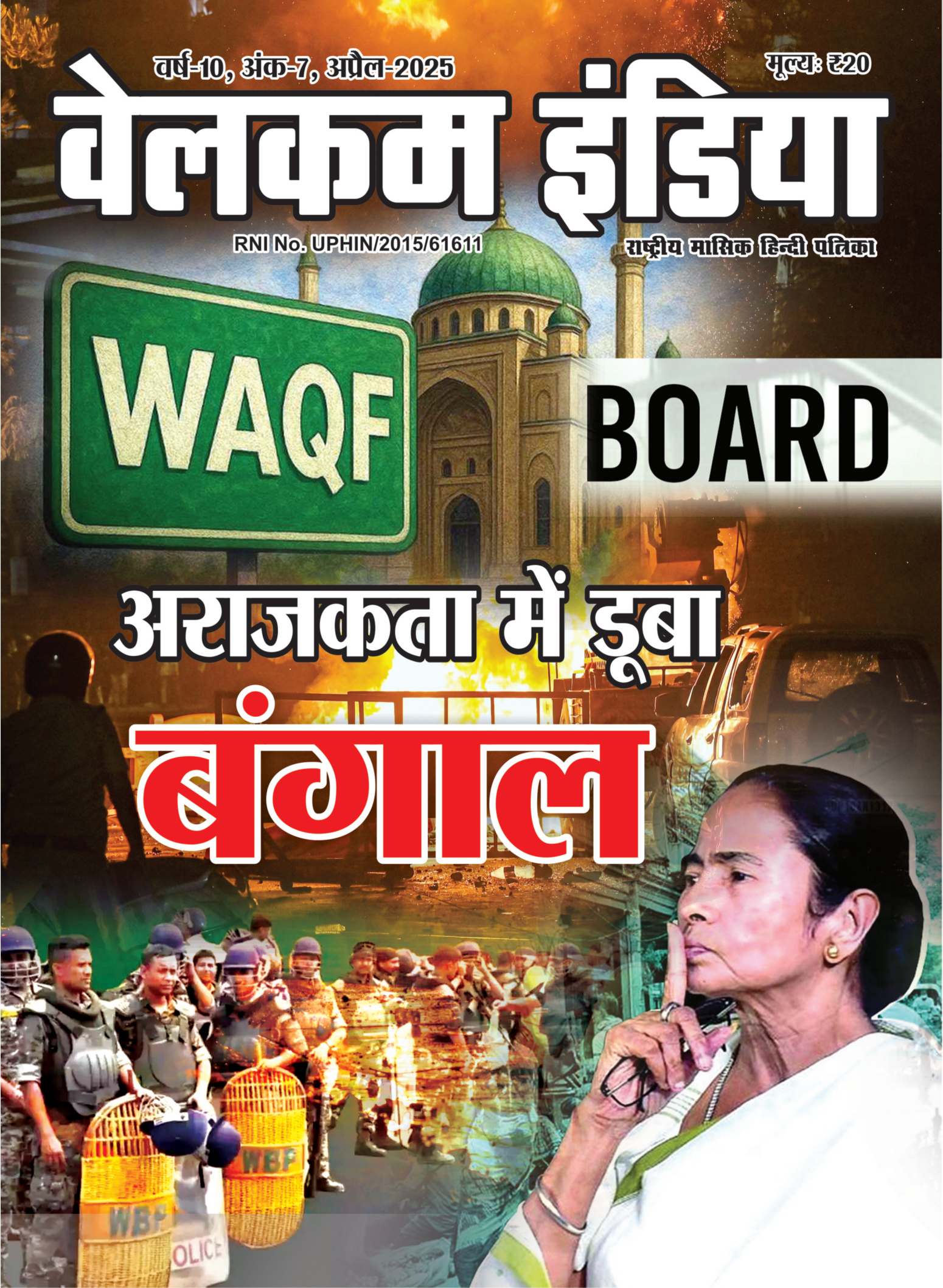

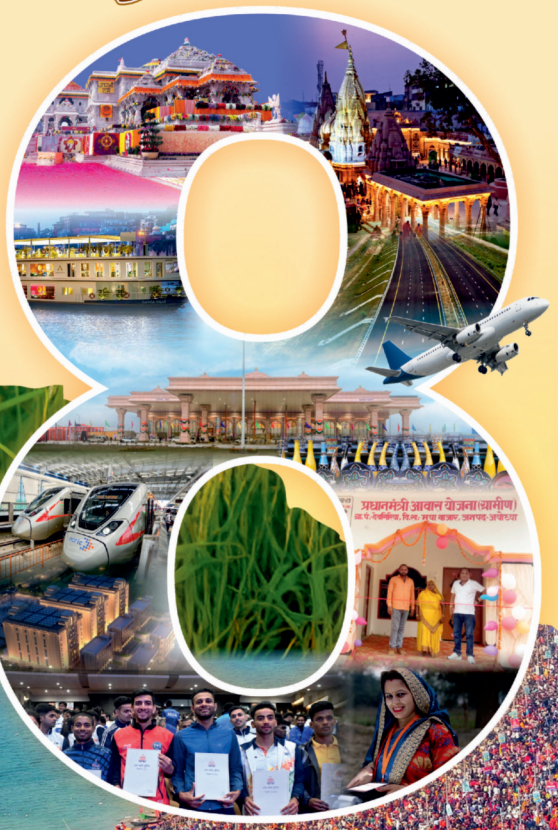

उत्कर्ष के
8
वर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
सबका साथ
सबका विकास
8 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय ₹46 हजार से बढ़कर ₹1 लाख 24 हजार
पहली कैबिनेट का पहला निर्णय: ₹36,359 करोड़ से 94 लाख किसानों का ऋण मोचन
पीएम किसान सम्मान निधि से 2.86 करोड़ किसानों को ₹80 हजार करोड़
GIS में ₹45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, ₹15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.86 करोड़ नि:शुल्क गैस कनेक्शन में यूपी प्रथम
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 22.11 लाख बालिकाएं लाभान्वित
6 एक्सप्रेसवे संचालित 11 पर काम जारी, 21 एयरपोर्ट
2016 में 21 करोड़ की तुलना में 2024 में 66 करोड़ पर्यटक यूपी आए
महाकुम्भ 2025 से अर्थव्यवस्था में ₹3.50 लाख करोड़ की अनुमानित वृद्धि
8 वर्षों में 204 करोड़ पौधरोपण, 2 लाख एकड़ में हरीतिमा बढ़ी
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

अन्दर के पेजों में...

वर्ष- 10 अंक- 7

अप्रैल -2025

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

पेज-28

कवर स्टोरी

भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में सांस्कृतिक... पेज 03

काशी और अयोध्य बनीं लाखों लोगों के लिए रोजगारनगरी पेज 08

जजों की संपत्ति का प्रकटीकरण पारदर्शिता की ओर कदम पेज 14

पुलिस कमिश्नर जे. रविन्द्र गौड़ ईमानदारी, न्यायप्रिय व कर्तव्यनिष्ठता की मिसाल पेज 15

भारत की टैरिफ कूटनीति के लाभ... पेज 18

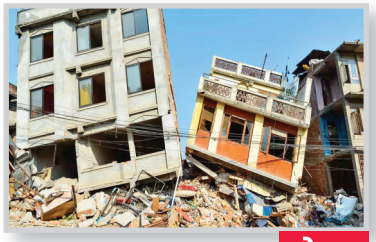

शहरी विकास के लिए चेतावनी है यह भूकंप... पेज 21

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

पश्चिम बंगालः चुनावों के वक्त हमेशा बढ़ जाता है खूनी संघर्ष

ललित कुमार
सम्पादक

पश्चिम बंगाल में दंगों पर खुल कर सियासत शुरू हो गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो उठा, उसमें तीन लोग मारे गए, कई दुकानों में तोड़-फोड़ की गई, कई जला दी गईं। उसे लेकर बंगाल में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वहां हिंसा करने वाले बाहर से लाए गए थे। उसके जवाब में भाजपा ने कथित खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि दंगा फैलाने वाले बांग्लादेश से आए थे। उसके वीडियो भी जारी किए गए।

फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दंगाइयों और ममता बनर्जी के खिलाफ तल्ख बयानबाजी शुरू कर दी। मगर ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों के वीडियो प्रसारित कर राज्य में अशांति फैलाना चाहती है। इस तरह की सियासी बयानबाजियों के शोर में यह हकीकत परदे की ओट में खिसकती जा रही है कि आखिर दंगा किन लोगों ने भड़काया था। उन लोगों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश धीमी पड़ती नजर आने लगी है। हालांकि राज्य सरकार और पुलिस का दावा है कि वह जल्दी दोषियों की पहचान कर उचित कार्रवाई करेगी।

पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संघर्ष और इस तरह सांप्रदायिक आधार पर हिंसक झड़पों का सिलसिला कुछ बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि ऐसे प्रयास पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में अधिक देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते, जब संदेशखाली में भी लंबे समय तक सांप्रदायिक तनाव बना रहा। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के आदमी उन्हें उठा कर ले जाते थे और उनका यौन शोषण किया जाता था।

मगर बाद में वह आरोप गलत साबित हुआ। चुनावों के वक्त तो वहां खूनी संघर्ष हमेशा बढ़ जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय अदालत के निर्देश पर निर्वाचन आयोग को अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम करने पड़े थे। अब फिर विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में कई लोगों का यह कहना गलत नहीं ठहराया जा सकता कि उसी के मद्देनजर रणनीति बनाई जा रही है। मगर सवाल है कि किसी भी राज्य में इस तरह अगर कुछ उपद्रवी कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हैं, तो सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकती है। मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में जो लोग मारे गए, घायल हुए, जिन लोगों की दुकानें जला दी गईं, जिनके रोजी-रोजगार के जरिया प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति आखिरकार किसकी जवाबदेही बनती है।

सांप्रदायिक तनाव किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और जिम्मेदार सरकार की निशानी नहीं माना जा सकता। जिस तरह वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में विरोध का वातावरण था और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में इसका विरोध उग्र होने की संभावना अधिक थी, उसमें सरकार से अपेक्षा की जाती थी कि अतिरिक्त सजगता बरते। मगर ऐसा नहीं हुआ, और अब उसे सियासी रंग देकर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह ठीक है कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की नाकामियों पर अंगुली उठाने का अधिकार है, मगर उससे भी सांप्रदायिक मामलों में संयम बरतने और सांविधानिक मूल्यों के पालन की अपेक्षा की जाती है। अगर सियासी फायदे के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं, जिससे सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति बनती है, तो उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता।

सांप्रदायिक तनाव किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और जिम्मेदार सरकार की निशानी नहीं माना जा सकता। जिस तरह वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में विरोध का वातावरण था और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में इसका विरोध उग्र होने की संभावना अधिक थी, उसमें सरकार से अपेक्षा की जाती थी कि अतिरिक्त सजगता बरते। मगर ऐसा नहीं हुआ, और अब उसे सियासी रंग देकर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में सांस्कृतिक संगठनों को भी निभानी होगी विशेष भूमिका

प्राचीनकाल में भारत में राजा का यह कर्तव्य होता था कि उसके राज्य में निवास कर रही प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और यदि किसी राज्य की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो वह नागरिक अपने कष्ट निवारण के लिए राजा के पास पहुंच सकता था।

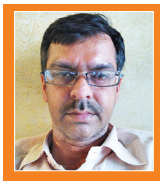

संजीव कुमार

प्राचीनकाल में भारत विश्व गुरु रहा है इस विषय पर अब कोई शक की गुंजाईश नहीं रही है क्योंकि अब तो पश्चिमी देशों द्वारा पूरे विश्व के प्राचीन काल के संदर्भ में की गई रिसर्च में भी यह तथ्य उभरकर सामने आ रहे हैं। भारत क्यों और कैसे विश्व गुरु के पद पर आसीन रहा है, इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि भारत में हिंदू सनातन संस्कृति के नियमों के आधार पर भारतीय नागरिक समाज में अपने दैनंदिनी कार्य कलाप करते रहे हैं। साथ ही, भारतीयों के डीएनए में आध्यतम पाया जाता रहा है जिसके चलते वे विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले अपने कार्यों को धर्म से जोड़कर करते रहे हैं। लगभग समस्त भारतीय, काम, अर्थ एवं कर्म को भी धर्म से जोड़कर करते रहे हैं। काम, अर्थ एवं कर्म में चूंकि तामसी प्रवृत्ति का आधिक्य बहुत आसानी से आ जाता है अतः इन कार्यों को तासमी प्रवृत्ति से बचाने के उद्देश्य से धर्म से जोड़कर इन कार्यों को सम्पन्न करने की प्रेरणा प्राप्त की जाती है। जैसे, भारतीय शास्त्रों में काम में संयम रखने की सलाह दी जाती है तथा अर्थ के अर्जन को बुरा नहीं माना गया है परंतु अर्थ का अर्जन केवल अपने स्वयं के हित के लिए करना एवं इसे समाज के हित में उपयोग नहीं करने को बुरा माना गया है। इसी प्रकार, दैनिक जीवन में किए जाने वाले कर्म भी यदि धर्म आधारित नहीं होंगे तो जिस उद्देश्य से यह मानव जीवन हमें प्राप्त हुए है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी।

प्राचीनकाल में भारत में राजा का यह कर्तव्य होता था कि उसके राज्य में निवास कर रही प्रजा

को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और यदि किसी राज्य की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो वह नागरिक अपने कष्ट निवारण के लिए राजा के पास पहुंच सकता था। परंतु, जैसे जैसे राज्यों का विस्तार होने लगा और राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो उस राज्य में निवास कर रहे नागरिकों के कष्टों को दूर करने के लिए धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन भी आगे आने लगे एवं नागरिकों के कष्टों को दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगे। समय के साथ साथ धनाडय वर्ग भी इस पावन कार्य में अपनी भूमिका निभाने लगा। फिर, और आगे के समय में एक नागरिक दूसरे नागरिक की परेशानी में एक दूसरे का साथ देने लगे। परिवार के सदस्यों के साथ पड़ौसी, मित्र एवं सहृदयी नागरिक भी इस प्रक्रिया में अपना हाथ बंटाने लगे। इस प्रकार प्राचीन भारत में ही व्यक्ति, परिवार, पड़ौस, ग्राम, नगर, प्रांत, देश एवं पूरी धरा को ही एक दूसरे के सहयोगी के रूप में देखा जाने लगा। 'वसुधैव कुटुंबकम', 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय', 'सर्वे भवंतु सुखिनः' का भाव भी प्राचीन भारत में इसी प्रकार जागृत हुआ है। 'व्यक्ति से समष्टि' की ओर, की भावना केवल और केवल भारत में ही पाई जाती है।

वर्तमान काल में लगभग समस्त देशों में चूंकि समस्त व्यवस्थाएं साम्यवाद एवं पूंजीवाद के नियमों पर आधारित हैं, जिनके अनुसार, व्यक्तिवाद पर विशेष ध्यान दिया जाता है और परिवार तथा समाज कहीं पीछे छूट जाता है। केवल मुझे कष्ट है तो दुनिया में कष्ट है अन्यथा किसी और नागरिक के कष्ट पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। जैसे यूरोपीयन देश उनके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर पूरे विश्व का आ'ान करते हुए पाए जाते हैं कि जैसे उनकी समस्या पूरे विश्व की समस्या है परंतु जब इसी प्रकार की समस्या किसी अन्य देश पर आती है तो यूरोपीयन देश उसे अपनी समस्या नहीं मानते हैं। यूरोपीयन देशों में पनप रही आतंकवाद की समस्या पूरे विश्व में आतंकवाद की समस्या मान ली जाती है। परंतु, भारत द्वारा झेली जा रही आतंकवाद की समस्या यूरोप के लिए आतंकवाद नहीं है। यह पश्चिमी देशों के डीएनए में है कि विकास की राह पर केवल मैं ही आगे बढ़ूँ, जबकि भारतीयों के डीएनए में है कि सबको साथ लेकर ही विकास की राह पर आगे बढ़ा जाय। यह भावना भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों में भी कूट कूट कर भरी है। इसी तर्ज पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। संघ के लिए राष्ट्र प्रथम है, और भारत में निवास करने वाले हम समस्त नागरिक हिंदू हैं, क्योंकि भारत में निवासरत प्रत्येक नागरिक से सनातन संस्कृति के संस्कारों के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। भले ही, हमारी पूजा पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु संस्कार तो समान

भारतीय शास्त्रों में काम में संयम रखने की सलाह दी जाती है तथा अर्थ के अर्जन को बुरा नहीं माना गया है परंतु अर्थ का अर्जन केवल अपने स्वयं के हित के लिए करना एवं इसे समाज के हित में उपयोग नहीं करने को बुरा माना गया है।

ही रहने चाहिए। इसी विचारधारा के चलते आज संघ देश के कोने कोने में पहुंचने में सफल रहा है। संघ ने न केवल राष्ट्र को एकजुट करने का काम किया है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय तथा उसके बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों में भी अपनी सक्रिय भूमिका सफलतापूर्वक निभाई है। इस वर्ष संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है परंतु संघ इसे अपनी उपलब्धि बिल्कुल नहीं मानता है बल्कि संघ के लिए तो शताब्दी वर्ष भी जैसे स्थापना वर्ष है और उसी उत्साह से अपने कार्य को विस्तार तथा सुदृढीकृत करते हुए आगे बढ़ने की बात कर रहा है। संघ का अपनी 100 वर्षों की स्थापना सम्बंधी उपलब्धि को उत्सव के रूप में मनाने का विचार नहीं है बल्कि इस उपलक्ष में संघ के स्वयंसेवकों से अपेक्षा की जा रही है कि वे आत्मचिंतन करें, संघ कार्य के लिए समाज द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार प्रकट करें एवं राष्ट्र के लिए समाज को संगठित करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें। शताब्दी वर्ष में समस्त स्वयंसेवकों से अधिक सावधानी, गुणवत्ता एवं व्यापकता से कार्य करने का संकल्प लेने हेतु आग्रह किया जा रहा है।

आज संघ कामना कर रहा है कि पूरे विश्व में निवास कर रहे प्राणी शांति के साथ अपना जीवन यापन करें एवं विश्व में लड़ाई झगड़े का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अतः हिंदू सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में फैलाव, इस धरा पर निवास कर रहे समस्त प्राणियों के हित में है। इस संदर्भ में आज हिंदू सनातन संस्कृति को किसी भी प्रकार का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो विकसित देशों द्वारा की जा रही रिसर्च में भी इस प्रकार के तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं कि भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है और यह हिंदू सनातन संस्कृति के अनुपालन से ही सम्भव हो सका है। अतः आज विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हिंदू सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में ही फैलाने की आवश्यकता है। परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने भी संघ की स्थापना के समय कहा था कि संघ कोई नया कार्य शुरू नहीं कर रहा है, बल्कि कई शताब्दियों से चले आ रहे काम को आगे बढ़ा रहा है। संघ का यह स्पष्ट मत है कि धर्म के अधिष्ठान पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण संगठित सामूहिक जीवन के आधार पर ही हिंदू समाज अपने वैश्विक दायित्व का निर्वाह प्रभावी रूप से कर सकेगा। अतः हमारा कर्तव्य है कि सभी प्रकार के भेदों को नकारने वाला समरसता युक्त आचरण, पर्यावरण पूरक जीवनशैली पर आधारित मूल्याधिशिष्ठ परिवार, स्व बोध से ओतप्रोत और नागरिक कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्ध समाज का निर्माण करें एवं इसके आधार पर समाज के सब प्रश्नों का समाधान, चुनौतियों का उत्तर देते हुए भौतिक समृद्धि एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण समर्थ राष्ट्रजीवन खड़ा करें। संघ का यह भी स्पष्ट मत है कि हिंदुत्व की रक्षा और उसका सशक्तिकरण ही विश्व में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 99 वर्षों की साधना के बाद संघ का प्रभाव देश में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और राष्ट्र का कायाकल्प हो रहा है। राष्ट्रीयता, स्व-पहचान, स्वदेशी भावना और हिंदू संस्कृति को ऊर्जा के स्त्रोतों के रूप में पुनर्परिभाषित करने के प्रयास तेज हो चुके हैं।

उक्त संदर्भ में संघ द्वारा नवम्बर 2025 से जनवरी 2026 के दौरान किन्हीं तीन सप्ताह तक बड़े पैमाने पर घर घर सम्पर्क अभियान की योजना बनाई गई है, इसका विषय 'हर गांव, हर बस्ती, हर घर' होगा। साथ ही, संघ द्वारा समस्त मंडलों और बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में एकता और सद्भाव, राष्ट्र के विकास में सभी का योगदान और पंच परिवर्तन में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, का संदेश दिया जाएगा। प्रत्येक खंड एवं नगर स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, इन बैठकों में एक साथ मिलकर रहने पर बल दिया जाएगा। इन बैठकों का उद्देश्य सांस्कृतिक आधार और हिंदू चरित्र को खोए बिना आधुनिक जीवन जीने का संदेश देना होगा। प्रयागराज में हाल ही में सम्पन्न महाकुम्भ में समस्त क्षेत्रों में लोग एक साथ आए थे, किसी को भी किसी नागरिक की जाति, मत, पंथ, आदि की जानकारी नहीं थी। विभिन्न नगरों के संभ्रांत नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसी प्रकार, युवाओं के लिए भी राष्ट्र निर्माण, सेवा गतिविधियां एवं पंच परिवर्तन पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना विभिन्न प्रांतों द्वारा तैयार की जा रही है। आज भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों को भी आगे आकर मां भारती को एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान देने की आवश्यकता है।

यूपी बनेगा देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे 2030 तक देश की नंबर वन अर्थव्यस्था वाला राज्य बनाने को कृत संकल्पित हैं। अभी एक अप्रैल को भी बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात को दोहराया था।

चरण सिंह

उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति देश भर में चर्चा का विषय है। प्रकृति एवं परमात्मा की असीम अनुकंपा के बावजूद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सातवें या आठवें स्थान पर झूलती रही। इस दौरान इसका कुल आकार भी 12 हजार करोड़ रुपये से लेकर 12.5 हजार करोड़ रुपये के बीच ही रहा। पर, मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें अभूतपूर्व बदलाव आया।

आज 27.5 हजार करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ यूपी देश की देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2 फीसद है। जीडीपी की ग्रोथ राष्ट्रीय औसत 9.6 फीसद की तुलना में 11.6 फीसद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे 2030 तक देश की नंबर वन अर्थव्यस्था वाला राज्य बनाने को कृत संकल्पित हैं। अभी एक अप्रैल को भी बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात को दोहराया था।

अब तो निजी तौर पर आर्थिक विशेषज्ञ और संस्थाएं भी यह मानने लगी हैं कि उत्तर प्रदेश में विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है। हाल ही में लखनऊ में योजना विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने भी यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि करीब 56 फीसद युवा आबादी, नौ तरह के अलग कृषि जलवायु क्षेत्र, पानी की भरपूर उपलब्धता आदि के जरिये यह संभव है।

उन्होंने अलग-अलग जिलों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए जिस एक्शन प्लान का जिक्र किया था, उस पर योगी सरकार पहले से काम कर रही है। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना और एक जिला-एक जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) इसकी कड़ी है। अब तो सरकार इससे भी आगे एक जिला एक पकवान के बाबत सोच रही है। ओडीओपी योजना प्रदेश की सफलतम योजना है। इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर कर चुके हैं। इंडोनेशिया जैसे देश भी इसकी इसके मुरीद हैं।

अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों पर एक नजर

नीति आयोग ने राजकोषीय स्थित के संबंध में जारी रिपोर्ट में यूपी को फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ ने भी कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरे स्थान पर रखा है। पिछले पांच वर्षों से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट की स्थित इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने प्रभावी तरीके से कर चोरी, इसके लीकेज को खत्म किया है। इसमें डिजिटलाइजेशन को बढ़ाकर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

ऋण और जमा अनुपात (सीडी रेशियो) जो हर दम से प्रदेश की समस्या रही है उसमें भी अच्छा खासा सुधार हुआ है। 2016/2017 में यह 46 फीसद था। 2024 में बढ़कर 61 फीसद हो गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार ने इसके लिए 67 से 70 फीसद का लक्ष्य रखा है। अर्थव्यवस्था में सुधार होने से बैंकों ने भी उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में रुचि दिखाई है। आरबी आई की अगस्त 2023 की बुलेटिन के अनुसार फंड आकर्षित करने में 16.2 फीसद की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। समग्रता में आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के मुताबिक उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ चौतरफा प्रयास जारी है।

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने में जुटी योगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने युवाओं के लिए एक नई क्रांति की शुरूआत की है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया और मनोरंजन जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में युवाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य कौशल विकास मिशन ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। प्रदेश में उभरते क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मनोरंजन, और नागरिक उड्डयन में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इन सेक्टर्स में विशेष कौशल प्रशिक्षण योजनाओं की शुरूआत की है। इसके साथ ही, जेवर एयरपोर्ट और फिल्मसिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स में रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल्स के माध्यम से युवाओं के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूरी भी कर ली गई है। सीएम योगी की यह दूरदर्शी कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

उभरते सेक्टर्स में युवाओं को मिल रहा विशेष प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने युवाओं के लिए एक नई क्रांति की शुरूआत की है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया और मनोरंजन जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में युवाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर सरकार युवाओं को 'रेडी टू वर्क' बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो प्रदेश में एयरपोर्ट के विकास के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता से जेवर एयरपोर्ट और फिल्मसिटी प्रोजेक्ट्स राज्य के विकास का आधार बन रहे हैं। इन परियोजनाओं के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल्स ने संभावित रोजगार क्षेत्रों की पहचान कर ली है, और अब प्रशिक्षित युवा इनके क्रियान्वयन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जबकि फिल्मसिटी नोएडा में मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देगी, जिससे मीडिया और प्रोडक्शन से जुड़े युवाओं को फायदा होगा। जेवर एयरपोर्ट और फिल्मसिटी से जुड़े प्रशिक्षण से युवा तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएंगे। यह कदम राज्य की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करेगा।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 14 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को मुफ्त और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य हर युवा को उसके कौशल के आधार पर रोजगार देना है। मिशन के तहत 2800 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों में हर साल तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो राज्य की विकास यात्रा को गति देगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से मार्च 2025 तक बीते आठ वर्षों में कुल 14,13,716 युवाओं को प्रतिशित किया गया है। साथ ही मिशन द्लारा 5,66,483 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। यही नहीं उत्तर प्रदे कौशल विकास मिशन द्वारा बीते आठ वर्षों में उत्पादन और सेवा क्षेत्र से जुड़े 24 प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों को फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाताओं को अनुबंधित किया गया है। इसके अलावा 8 प्लेसमेंट एजेंसीज को भी अनुबंधित किया गया है।

काशी और अयोध्य बनीं लाखों लोगों के लिए रोजगारनगरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सच साबित कर दिया। आज शिव की अविनाशी काशी और राम की अयोध्या पर्यटकों की आमद के मद्देनजर यहां के लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया बन गए हैं। कमोबेश यही स्थिति अन्य तीर्थ स्थलों की भी है। तीरथराज प्रयाग में आयोजित महाकुंभ में तो इसका चरमोत्कर्ष दिखा।

राहुल अग्रवाल

अपने यहां कहा जाता है, 'जिसने जन्म दिया वही रोटी का भी इंतजाम करेगा'। यह ऊपरवाले पर मुकम्मल भरोसे के साथ इस बात की ओर भी संकेत करता है कि अगर अपने इष्टदेवों से जुड़े स्थलों को सजा सवार दिया जाय। वहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर बुनियादी सुविधाएं विकसित कर दी जाएं तो वहां भारी संख्या में रोजी रोजगार के अवसर स्थानीय और आसपास के लोगों को उपलब्ध होते हैं। यह राम को रोटी को जोड़ने जैसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सच साबित कर दिया। आज शिव की अविनाशी काशी और राम की अयोध्या पर्यटकों की आमद के मद्देनजर यहां के लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया बन गए हैं। कमोबेश यही स्थिति अन्य तीर्थ स्थलों की भी है। तीरथराज प्रयाग में आयोजित महाकुंभ में तो इसका चरमोत्कर्ष दिखा। सरकार का अनुमान था कि करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक समागम में करीब 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु एवं पर्यटक शामिल होंगे, पर शामिल हुए 66 करोड़ से अधिक लोग। इनमें से बहुतों की मंजिल सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, काशी, अयोध्या, वनगमन

के दौरान जहां भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित राम को निषादराज ने जहां उनको गंगा पार कराया था वह श्रृंगवेरपुर और वनगमन के दौरान राम ने मंदाकिनी के तट पर जिस चित्रकूट में सर्वाधिक समय गुजारा था, वह भी थी। कई लोगों ने विंध्याचल स्थित मां जगदंबा के दरबार में भी हाजिरी लगाई। ब एक पर्यटक ने औसतन इस दौरान कितना खर्च किया। इस खर्च का कितना कितना लाभ इस सेक्टर्स से जुड़े स्टेकहोल्डर्स और स्थानीय लोगों को मिला। केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से में प्रयागराज के महाकुंभ और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और राममंदिर एवं अयोध्या के कायाकल्प पर हुए खर्च की तुलना में कितना लाभ हुआ, यह अर्थशास्त्र के जानकारों के लिए अनुमान विषय है। पर, यह निर्विवाद सच है कि पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद से लाभ में सब रहे। साथ ही इसने उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाओं का एक नया और बड़ा दरवाजा खोल दिया। क्योंकि, बहुसंख्यक समाज के रोम रोम में बसने वाले राम की अयोध्या, तीनों लोकों से न्यारी शिव की काशी और राधा कृष्ण की जन्म भूमि, ग्वाल बालों और गोपियों के साथ लीला के स्थल ब्रज उत्तर प्रदेश में है। इन सभी जगहों की संभावनाओं के मद्देनजर योगी सरकार यहां आने वालों की सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से लगातार काम भी कर रही है।

तीन साल से घरेलू पर्यटकों के आमद के हिसाब से यूपी देश में नंबर वन

इसका नतीजा है कि पर्यटकों की आमद के हिसाब से उत्तर प्रदेश लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2022 से ही घरेलू पर्यटकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर बना हुआ है। सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र 24 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 65 करोड़ हो गई। आठ वर्षों में 41 करोड़ की यह वृद्धि खुद में अभूतपूर्व है। स्वाभाविक है कि महाकुंभ के नाते 2025 एक नया रिकॉर्ड रचेगा। यह संख्या एक अरब का ऊपर तक जा सकती है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 फीसद से अधिक घेरलू यात्राएं धार्मिक स्थलों की होती हैं। धार्मिक पर्यटन आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए ऐसी सभी जगहों को बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं, सड़क और एयर कनेक्टिविटी, आने वालों की सुरक्षा और सेवा देनी होती है। यह सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संजीदगी से कर रही है।

आठ वर्षों की मेहनत का नतीजा है पर्यटन क्षेत्र का ये उभार

यह सब यूं ही नहीं हुआ। इसकी पृष्ठभूमि मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तभी से शुरू हो गई थी। तब अयोध्या जाना तो दूर की बात, कोई नेता अयोध्या का नाम तक नहीं लेना चाहता था उस अयोध्या में वह बार बार गए। हर बार उन्होंने अयोध्या को विकास की बड़ी सौगात दी। दीपावली के एक दिन पूर्व भव्य दीपोत्सव आयोजन कराया। इससे एक बार फिर देश-दुनिया में राम को मानने वालों का ध्यान अयोध्या की ओर गया। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और मंदिर का शिलान्यास होने के बाद तो केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। मुख्यमंत्री की मंशा अयोध्या की दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी बनाने की है। इसे वे कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कह चुके हैं। उसी मंशा के अनुरूप अयोध्या में लगातार काम भी हो रहे है। काशी, प्रयाग, ब्रज क्षेत्र पर भी उनका इसी तरह

नीति, दृढ़संकल्प व करिश्माई नेतृत्व के दम पर राजनीति के शिखर पर भाजपा

भाजपा ने एक राजनैतिक दल के रूप में शुरूआत से लेकर के आज तक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय एवं जनहित के मुद्दों को बहुत ही दमदार ढंग से उठाते हुए, देश के आम जनमानस के बीच बेहद ही कम समय में अपनी एक सशक्त पहचान बनाने का कार्य किया है।

रवि जैन

'सबका साथ, सबका विकास' की विचारधारा से ओतप्रोत हो सशक्त, सुदृढ़, समृद्ध, समर्थ, स्वावलम्बी एवं विश्वगुरु भारत के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा व ईमानदारी से समर्पित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 6 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मना रही है, भाजपा के प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जिले, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखलाएं चलाई जा रही है, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा की विचारधारा व केंद्र व भाजपा शासित राज्य सरकारों की नीतियों को लेकर के अधिक से अधिक लोगों के पास कैसे पहुंचा जाएं, देश व प्रदेशों का भाजपा नेतृत्व इसकी रणनीति निरंतर बना रहा है। वह अब भी यह देखकर संतुष्ट नहीं हैं कि उसने केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर के इतिहास रचने का कार्य कर दिया है, आज भी भाजपा के नेता व कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पार्टी को ओर मजबूत करने में दिन-रात लगें हुए हैं, जो भाजपा संगठन की एक बहुत ही बड़ी खूबी है और उसको अन्य पार्टियों से अलग बनाती है।

देश की आजादी के बाद कभी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कुशल मार्गदर्शन में शून्य से अपनी राजनीति की शुरूआत करने वाली जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी तक का सफर करते हुए भाजपा की स्थापना और फिर उसको देश व दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने तक के कठिन सफर में भाजपा के लाखों करोड़ों निस्वार्थ भाव से लगे हुए संगठन शिल्पी नेताओं व कार्यकताओं का बहुत ही अहम अनमोल योगदान रहा है, उन लोगों की त्याग, तपस्या, लगन, मेहनत, बलिदान से भाजपा आज इस मुकाम पर खड़ी है। भाजपा के

कार्यकताओं की इस मेहनत के इतिहास से भारत की राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को रूबरू अवश्य होना चाहिए। अस्सी के दशक में जनता पार्टी से अलग होकर के किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी व उनके अन्य सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी का देश में विस्तार करने का एक सपना देखा था और उस सपने को उन सभी ने मिलकर के धरातल पर साकार करते हुए केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन करने वाले अहम मुकाम तक पहुंचाने का कार्य बखूबी से किया था।

वहीं इस सपने को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने आगे बढ़ाते हुए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर देश में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों का एक-एक करके स्थाई समाधान करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करना निरंतर जारी रखा हुआ है। भाजपा दशकों के बाद आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म-मानवदर्शन' को अपने वैचारिक दर्शन के सिद्धांतों पर पूरी तरह से अमल करती है। भाजपा का हमेशा अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष जोर रहा है, जो देश व समाज के हित में पूरी तरह से उचित है। भाजपा ने पांच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की, पांच सिद्धांत राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद तथा मूल्य आधारित राजनीति करना हैं।

अपने सिद्धांतों के चलते ही स्थापना के समय से ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उसके पास पार्टी व देशभक्ति की विचारधारा से ओतप्रोत राजनेताओं की एक लंबी जमात हमेशा रही है। पार्टी के लाखों कार्यकताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के. जना कृष्णामूर्ति, एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा के कार्यकाल का दौर निकट से देखा है और अटल बिहारी वाजपेयी व नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी देखा है, सभी का ₹राष्ट्र प्रथम₹ का ही उद्देश्य मुख्य रहा है। भाजपा के कार्यकताओं ने पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक भी भाजपा को कभी किसी एक परिवार व व्यक्ति की बपौती नहीं बनने दिया है, पार्टी में आज भी आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। देश व दुनिया में भाजपा की पहचान एक ऐसे राष्ट्रवादी राजनैतिक दल के रूप होती है, जिसका

ध्येय देश में सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कार्य करना है।

भाजपा ने एक राजनैतिक दल के रूप में शुरूआत से लेकर के आज तक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय एवं जनहित के मुद्दों को बहुत ही दमदार ढंग से उठाते हुए, देश के आम जनमानस के बीच बेहद ही कम समय में अपनी एक सशक्त पहचान बनाने का कार्य किया है। साथ ही बीतते हुए समय के साथ भाजपा के कर्ताधताओं ने अपनी चाणक्य नीति व कुशल-कारगर ठोस रणनीति के दम पर देश की राजनीति व लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दर्ज करते हुए बहुत सारे राज्यों व केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बना कर देश की राजनीति को नए आयाम देने का कार्य करते हुए, देश के आम जनमानस के दिलो-दिमाग पर छा जाने का कार्य बखूबी किया है।

भारत के राजनैतिक इतिहास को देखें तो यह स्पष्ट रूप से नजर आता है कि वर्ष 2014 से देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाने का काम किया है, बल्कि भाजपा के नाम देश व दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का कीर्तिमान भी दर्ज हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगभग 11 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गई है। भाजपा आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व अमित शाह की जोड़ी के करिश्माई नेतृत्व में आज एक ऐसा बेहद विशाल वट वृक्ष बन गई है, जिस पर भरोसा करते हुए देश की लगभग 50 से 60 फीसदी के करीब आबादी सकून से जीवन यापन कर रही है।

नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में वर्ष 2014 में पहली बार केंद्र में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने अवसर मिला था। जिसके बाद से ही भाजपा ने ₹सबका साथ, सबका विकास₹ के सिद्धांत पर अमल करते हुए देश के नव निर्माण का अभियान शुरू कर रखा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बहुत ही कम समय में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने का कार्य किया है। मोदी सरकार ने विश्व भर में भारत की गरिमा को पुनःस्थापित करने का कार्य किया है। मोदी सरकार में अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश तेजी के साथ बढ़ चला है। आर्थिक और सामाजिक सुधार सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। केंद्र सरकार की किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी नीतियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलख जगायी है। मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन के नये युग का दौर चल रहा है। मोदी सरकार की चाहे आदर्श ग्राम योजना हो, स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वथ्य बनाने का अभियान, इन सभी कदमों से देश को एक नयी ऊर्जा मिली है। भाजपा की मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से देश को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जनधन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं, देश में केंद्र सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर विश्वस्तरीय अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है। राम मंदिर निर्माण, धारा 370, नोटबंदी, ट्रिपल तलाक, वक्फ बिल आदि भाजपा सरकार के दृढ़ संकल्प को दशार्ती हैं।

भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर लगता है कि वह एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय हैं, विदेशी नीति के मसले पर भारत सरकार अब विश्व शांति तथा एक न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भाजपा सरकार में भारत वैश्विक मंच पर दमदार ढंग से अपनी बात रखने की ताकत रखता है। भाजपा की कल्पना भारत को एक ऐसे ताकतवर राष्ट्र बनाने की है, जिसकी निवासी खुशहाल हो, जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं सनातन धर्म संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान विश्वशक्ति एवं विश्वगुरू के रूप में

देश में समाप्त होने के कगार पर पहुंचा नक्सलवाद

मगर अब परिस्थितियों पूरी तरह बदल चुकी है। केंद्र सरकार की नक्सलवाद से मुक्ति के अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है। कई बड़े-बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर अपनी जान बचा ली है।

पिछले छः दशकों से देश में नासूर बनकर उभरा नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्री द्वारा की गई यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। गत 60 वर्षों से देश नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह पीड़ित रहा है। इस दौरान देश में कई सरकारें आई और चली गई मगर नक्सलवाद का नासूर दिनों-दिन बढ़ता ही रहा था। देश के कई प्रदेशों में तो बहुत बड़े हिस्से में नक्सलवादी अपनी समानांतर सरकार तक चलाते थे। नक्सलवाद प्रभावित जिलों में उनकी हुकूमत चलती थी। वहां केंद्र व राज्य सरकार का कोई

इंद्रेश शर्मा

असर नहीं दिखता था। नक्सलियों का फरमान ही अंतिम आदेश होता था जिसे लोग मानने को मजबूर थे।

मगर अब परिस्थितियों पूरी तरह बदल चुकी है। केंद्र सरकार की नक्सलवाद से मुक्ति के अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है। कई बड़े-बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर अपनी जान बचा ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनो कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दिया है। शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर रोशनी डालते हुए और सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा था कि मोदी सरकार सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों और नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ रुख के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से

उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या पहले 38 थी। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 6 हो गई है। साथ ही चिंता के जिलों और अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों में अब छत्तीसगढ़ में चार जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला व महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला शामिल है। इसके अतिरिक्त चिंता के जिलों की संख्या जिन्हें गहन संसाधनों और ध्यान की आवश्यकता है 9 से घटकर 6 रह गई है। ये जिले आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश में बालाघाट, ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी और तेलंगाना में भद्राद्री-कोठागुडेम हैं।

अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या जो नक्सली गतिविधि का भी सामना कर रहे हैं लेकिन कम हद तक 17 से घटकर 6 हो गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चैकी, झारखंड का लातेहार, ओडिशा का नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल हैं। इन जिलों को उनके पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपये मिलते हैं। जबकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए चिंता वाले जिलों को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप विशेष परियोजनाओं को भी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में कम से कम 130 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 110 से ज्यादा बस्तर संभाग में मारे गए जिसमें बीजापुर और कांकेर समेत सात जिले शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 2025 में अब तक 164 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इससे पहले वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को

न्यूट्रलाइज किया जा चुका है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 जिले नक्सलप्रभावित थे लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004 से 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़ी 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 53 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। लेकिन पिछले 10 साल में सुरक्षाबलों के हताहत होने की संख्या 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई है। वहीं 2004 से 14 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच यह आंकड़ा 70 प्रतिशत घटकर 1495 रह गया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था।

पिछले 20 वर्षों में 2,344 सुरक्षाकर्मियों ने नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है पिछले दो दशकों में अकेले नक्सली हमलों में 6,258 लोग मारे गए हैं। जब देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था तब 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी थे। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैले एक लाल गलियारे के साथ 10 राज्यों में फैला हुआ था।

सरकार एक तरफ जहां नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा कर रही है वहीं दूसरी तरफ शहरी नक्सलवाद जिसे अर्बन नक्सलवाद भी कहा जाता है तेजी से उभर रहा है। यह पारंपरिक ग्रामीण नक्सलवाद से अलग है क्योंकि इसका फोकस शहरों और शहरी इलाकों में होता है। शहरी नक्सली विचारधारा के समर्थक, जिनमें शिक्षाविद, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं नक्सलवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते हैं। वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माध्यमों से अपनी विचारधारा फैलाते हैं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष को भड़काते हैं।

देश में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के समग्र प्रयासों का असर दिखने लगा है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी हो रही है। सरकार ने नक्सलवाद-मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देश में वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आना इस आंदोलन की समाप्ति के संकेत है।

नक्सलवादी आंदोलनकारियों ने अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने भी नक्सलवादी विरोधी अभियान में अपनी शहादत दी है। एक समय था जब देश के 10 प्रांतो में नक्सलवादियों की तूती बोलती थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी हमला कर दिया था। जगदलपुर में तो नक्सलवादियों ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की हत्या कर सनसनी फैला दी थी।

मगर अब केंद्र सरकार की नीतियों के कारण एक तरफ जहां इन पर दबाव बढ़ा है वहीं उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार ने विकास की योजनाएं प्रारंभ कर उनका जन समर्थन समाप्त कर दिया है। कई बड़े नक्सली कमांडरो का एनकाउंटर होने के बाद डर कर बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जिससे आने वाले समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति व्याप्त होगी। जो सरकार व आमजन की एक बड़ी जीत होगी।

अनिल वशिष्ठ

जजों की संपत्ति का प्रकटीकरण पारदर्शिता की ओर कदम

न्यायधीशों को भी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने का मुद्दा बहुत पुराना रहा है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार हर न्यायाधीश को अपनी प्रॉपर्टी और देनदारियों के बारे में चीफ जस्टिस को बताना होता है।

न्यायपालिका पर जनता का भरोसा लोकतंत्र का अहम आधार है। न्यायिक प्रणाली में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिये न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता, जबावदेही एवं निष्पक्षता की जरूरत है, इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय से निचली अदालतों तक के न्यायाधीशों को संपत्ति सार्वजनिक करने जैसे कदम उठाए जाने की अपेक्षा आजादी के अमृतकाल में तीव्रता से की जा रही थी, ताकि न्यायपालिका की पारदर्शिता को लेकर उठने वाले संदेह दूर हो सकें, यह मुद्दा जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर जली हुई नोटों की गड्डी मिलने जैसी घटनाओं और उनसे उपजे विवादों के बाद गंभीर सार्वजनिक विमर्श का बन गया था। जनचचाओं एवं आदर्श राष्ट्र-निर्माण की अपेक्षाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने पर जो सहमति जताई है, वह सही दिशा में उठाया गया उचित एवं प्रासंगिक कदम है। इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी और आम लोगों का उस पर भरोसा मजबूत होगा। देश में न्यायालयों को ऐसी संस्था के रूप में देखा जाता है, जो आम लोगों के लिए न्याय की आखिरी उम्मीद है। न्याय करने वाले न्यायाधीशों पर संदेह के बादल मंडराना न्याय-प्रक्रिया पर भरोसा कम करने का एक बड़ा कारण बनता रहा है। अब जनता की अपने पंच-परमेश्वरों की स्वच्छ-धवल छवि की आकांक्षा पूरी होते हुए दिखाई देना एक रोशनी बना है, जिससे न्याय प्रक्रिया के प्रति विश्वास ज्यादा मजबूत होगा। नया भारत बनाने एवं सशक्त भारत बनाने के लिये न्यायिक प्रक्रिया में सुधार एवं पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी ही चाहिए।

न्यायधीशों को भी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने का मुद्दा बहुत पुराना रहा है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार हर न्यायाधीश को अपनी प्रॉपर्टी और देनदारियों के बारे में चीफ जस्टिस को बताना होता है। बाद में, एक और प्रस्ताव आया कि न्यायाधीश चाहें तो अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन

यह अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक था। पिछले लगभग तीन दशक में, यह मामला कई बार उठा है। सूचना का अधिकार लागू होने के बाद यह बहस भी हुई कि न्यायपालिका इसके दायरे में क्यों नहीं? इसके पीछे यही तर्क रहा कि किसी निजी जानकारी को तब तक साझा करने की जरूरत नहीं, जब तक उससे सार्वजनिक हित न जुड़े हों।

2010 और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस आया था, तब इसी तथ्य को आधार बनाकर कहा गया कि जानकारी सार्वजनिक करना न्यायाधीशों की इच्छा पर है। एक तरह से यह व्यवस्था न्यायाधीशों को लगातार संदेहों के घेरे में रखती रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा का निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता कायम करने वाला एक सराहनीय कदम होगा। जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने की मांग के पीछे बड़ा तर्क भी यही दिया जाता रहा है कि जब तक जजों की संपत्ति सार्वजनिक नहीं होगी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों पर ठोस कार्रवाई संभव नहीं हो सकेगी। देश में न्याय की प्रक्रिया सहज, सरल पारदर्शी एवं समानतामूलक होने के साथ आम आदमी के भरोसे वाली होनी चाहिए। इसके लिये भारत की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण होना चाहिए। भारतीयकरण के लिये ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जबावदेही आवश्यक मूल्य है।

सरकार की एक संसदीय समिति ने 2023 में सिफारिश की थी कि न्यायाधीशों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य की जाए। हालांकि कतितय कारणों से सरकार इस मामले में आगे नहीं बढ़ी। इसका एक बड़ा कारण सरकार पर यह आरोप लगना भी बना कि सरकार न्यायपालिका में अनावश्यक राजनीतिक दखल दे रही है। लेकिन न्यायपालिका की साख के लिए उसका स्वतंत्र होना और दिखना भी जरूरी है। लेकिन सम्पत्ति की घोषणा के मामले में उन्हें अतिरिक्त सुविधा देना या उनके लिये अतिरिक्त सुविधा का होना, संदेह का कारण बनता रहा है।

दरअसल, वर्तमान परिपाटी के अनुसार न्यायाधीशों के लिये निजी संपत्ति का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना एक स्वैच्छिक परंपरा है। जिसे अनिवार्य बनाने की मांग की जाती रही है। निश्चय ही न्याय व्यवस्था के संरक्षक होने के कारण इसके स्वैच्छिक रहने पर तमाम किंतु-परंतु हो सकते हैं। यूं तो न्यायपालिका के कामकाज में कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। संपत्ति की घोषणा जैसे कई स्तरों पर न्यायिक सुधार के प्रयास आगे बढ़ाने की जरूरत नये भारत, सशक्त भारत एवं आदर्श भारत के लिये जरूरी है। अब अगर सर्वोच्च अदालत के जज खुद को भी उन कसौटियों पर कसने में नहीं हिचक रहे हैं जिन्हें वे दूसरों के लिए जरूरी मानते हैं, तो निश्चित ही इस कदम से एक सकारात्मक संदेश जरूर गया है।

न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से, सुप्रीम कोर्ट के सभी 30 मौजूदा न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति को न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करके सार्वजनिक रूप से प्रकट करने पर सहमति व्यक्त की है। यह घटनाक्रम न्यायपालिका में पारदर्शिता की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद हुआ है, खासकर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद के बाद। जिन न्यायाधीशों ने पहले ही अपनी घोषणाएं प्रस्तुत कर दी हैं, उनमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी शामिल हैं।

इसे फैसले को न्याय के प्रति जनता के भरोसे को और मजबूत करने के लिहाज से सही एवं सामयिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो सुखद होने के साथ-साथ श्रेयस्कर न्याय-प्रक्रिया का द्योतक है। निश्चय ही यह एक सार्थक पहल ही कही जाएगी। इस नवीनतम प्रस्ताव के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक रूप से संपत्ति के खुलासे को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाने का निर्णय लेकर जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत के अनेक पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल आदि में न्यायाधीश अपनी संपत्तियों की घोषणा करते हैं। कई देशों में यह स्वैच्छिक है तो कुछ जगह अनिवार्य भी है। न्यायपालिका ही फरियाद का अंतिम पड़ाव कहा जाता है। ऐसे में न केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बल्कि न्यायपालिका के सभी स्तरों पर न्यायाधीश अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करें तो इससे जनता को उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा। अब तक का अनुभव बताता है कि उच्च न्यायालयों के स्तर पर भी जजों में संपत्ति को सार्वजनिक करने की प्रवृत्ति काफी कम है। मार्च 2025 तक, उच्च न्यायालयों के कुल 763 में से सिर्फ 49 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है।

न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अभी इस दिशा में और प्रयासों की जरूरत है। निर्वाचित प्रतिनिधियों और नौकरशाहों को अपनी संपत्ति का सार्वजनिक खुलासा करना कानूनन अनिवार्य किया जा चुका है। ऐसे में आम जनमानस में धारणा बनी रहती है कि न्यायपालिका के बाबत भी कोई ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। यह प्रश्न न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता और जबावदेही से भी जुड़ा है। यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि विधि एवं न्याय विभाग की संसदीय समिति ने वर्ष 2023 में न्यायाधीशों के लिये अनिवार्य रूप से संपत्ति की घोषणा की सिफारिश की थी। लेकिन इस बाबत अभी तक कोई वैधानिक नियम नहीं बनाए गए हैं। लेकिन अब स्वयं न्यायपालिका की तरफ से ऐसी व्यवस्था लागू करने का सराहनीय प्रयास होना सुखद ही कहा जायेगा।

न्यायपालिका हमेशा से समाज में पारदर्शिता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता व शुचिता की पक्षधर रही है। जनता इस कसौटी पर अपने न्याय के देवताओं को भी खरा उतरता देखना चाहती है। निस्संदेह इस तरह के फैसले का समाज में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की दृष्टि से दूरगामी प्रभाव भी होगा। इस दिशा में ऐसी किसी भी पारदर्शी व्यवस्था का समाज में स्वागत ही होगा। ऐसे किसी भी कदम से उस आम आदमी के विश्वास को भी बल मिलेगा जो हर तरह के अन्याय व भ्रष्टाचार से तंग आकर उम्मीद की अंतिम किरण के रूप में न्यायालयों का रुख करता है। वह न्यायाधीशों को न्याय, सत्य व सदाचारिता के प्रतीक के रूप में देखता है। वो न्याय देने वालों को न्याय की हर कसौटी पर खरा उतरता हुआ भी देखना चाहता है। यह न्याय की शुचिता की भी अनिवार्य शर्त है। जब एक अकेले व्यक्ति का जीवन भी मूल्यों एवं जीवन-मानकों के बिना नहीं बन सकता, तब एक न्याय-व्यवस्था मूल्यों, निष्पक्ष मानकों, पारदर्शिता एवं समानता के बिना कैसे शक्तिशाली एवं विश्वसनीय बन सकती है?

पुलिस कमिश्नर जे. रविन्द्र गौड़

ईमानदारी, न्यायप्रिय व कर्तव्यनिष्ठता की मिसाल

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के रूप में जे. रविन्द्र गौड़ अपना कार्यभार संभालने के बाद जनपद पुलिस अधिकारियों के साथ पहली ही मीटिंग में साफ संकेत दे दिया कि उन्हें अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है। वे किसी के कार्य में हीला-हवाली व भ्रष्टाचार बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा व कर्तव्य परायणता के साथ निभाएं। वरिष्ठ आईपीएस जे. रविन्द्र गौड़ की विशेष कार्यशैली के चलते पुलिस विभाग में उनकी ईमानदारी, न्यायप्रियता व कर्तव्यनिष्ठता की मिसाल दी जाती है।

ललित कुमार

जे. रविन्द्र गौड़ की गिनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अधिकारियों में गिनी जाती है। प्रदेश सरकार की कर्तव्य निष्ठ अधिकारियों की सूची में इनका भी नाम शुमार है। यही कारण है उन्हें आगरा पुलिस कमिश्नर पद से तबादला करके गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर बनाकर भेजा गया है। वे आगरा में करीब 15 माह तक पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनात रहे और इस अवधि में उन्होंने आगरा में कानून का राज कायम रखने के लिए पुलिसिंग में कई तरह के प्रयोग किये, जो बेहद कारगर साबित हुए।

वर्ष -2005 बैच के आईपीएस जे. रविंद्र गौड़ मूलतः महबूब नगर, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आगरा में बतौर पुलिस कमिश्नर तैनाती से पहले वे गोरखपुर रेंज के आईजी पद पर तैनात थे। इससे पहले वे मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण जनपद में एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं वे आईजी एसआईटी लखनऊ के पद की दायित्व भी निभा चुके हैं।

तमाम महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती के दौरान अपनी विशेष कार्यशैली में अधीनस्थों से काम लेने में माहिर व कम से कम समय में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने व जनता का न्याय व राहत दिलाने में विश्वास रखने वाले गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के रुप में अपनी उपलब्धियों के खाते में क्या-क्या दर्ज कराते हैं, यह आने वाले

दिनों में ही पता चल सकेगा।

हालांकि पुलिस कमिश्नर जे. रविन्द्र गौड़ ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पहली मीटिंग में ही उन्हें अपने कड़क तेवरों से वाकिफ करा दिया था। विभाग के लापरवाह अधिकारियों के प्रति कड़क मिजाजी व आमजनता के लिए उनका सौम्य व्यवहार को लेकर पुलिस विभाग में चचाएं आम हैं। लापरवाह व भ्रष्टाचार प्रवृत्ति के अधिकारी घबराये हुए हैं। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि सभी अधिकारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालयों में जनसुनवाई करेंगे और यह औपचारिक न होकर जनता की समस्याओं को यथाशीघ्र समाधान कराने की दिशा में सार्थक प्रयास होना चाहिए, जिसका सुखद परिणाम आम जनता भी महसूस कर सके।

पुलिस प्रणाली में अभिनव प्रयोग की योगी सरकार ने की थी प्रशंसा

आगरा में बतौर पुलिस कमिश्नर जे. रविन्द्र गौड़ ने कई अभिनव प्रयोग करे। इन प्रयोग के कारण अपराधों में जबदस्त कमी आने से साथ ही आम जनता में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी। इस कारण में उन्होंने अपने 15 महीनों के कार्यकाल में तमाम उपलब्धियों को पुलिस के खाते में दर्ज कराया। उनके पुलिस प्रणाली में अभिनव प्रयोग से मिली सफलताकी योगी सरकार ने प्रशंसा की थी और अन्य जनपदों के पुलिस प्रमुखों को भी ऐसे ही प्रयोग करने की सलाह दी थी। उन्होंने साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली लागू कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कवायद की थी, जिसे सर्वत्र सराहा गया था।

गाजियाबाद में हैं नये पुलिस कमिश्नर के सामने हैं कई चुनौतियां

नि:संदेह नये पुलिस कमिश्नर जे. रविन्द्र गौड़ बहुत काबिल कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार आला अफसर हैं। लेकिन गाजियाबाद एक ऐसा शहर है, जिसका मिजाज समझना आसान नहीं हैं। देश की राजनीतिक दिल्ली के निकट का जनपद होने के नाते यहां की राजनीतिक, भौगौलिक, आर्थिक व सामाजिक स्थितियां भी प्रदेश के अन्य जनपदों से बिल्कुल अलग है। इस शहर में बसने वाले लोग अलग-अलग प्रांतों, जनपदों से ताल्लुक रखते हैं। इस कारण यहां की संस्कृति विविधा लिये हुए हैं। यहां अपराधी भी काफी हाईटेक हैं। अधिकांश बड़े अपराधों में लिप्त अपराधी स्थानीय न होकर बाहरी होते हैं और इन कुख्यात अपराधियों के तार दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा, राजस्थान आदि से जुड़े होने के कारण गाजियाबाद पुलिस को इनके नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कई तरह चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं गाजियाबाद के जनप्रतिनिधियों का सत्ता में पूरा दखल रहता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों में एक कैबिनेट मंत्री व एक राज्यमंत्री भी हैं। इसलिए पुलिस कमिश्नर के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों, विपक्षी दलों, सामाजिक संगठन व मीडिया के साथ भी तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि इन पहले तैनात रहे पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का जनप्रतिनिधियों, विपक्षी दलों, सामाजिक संगठन व मीडिया के साथ समन्वय बहुत अच्छा नहीं रहा। इसलिए वे समय-समय पर गाजियाबाद की जनता की विरोध व आलोचना झेलते रहे। नये पुलिस कमिश्नर जे. रविन्द्र गौड़ से इन सब स्थितियों से बचकर सभी के बेहतर तालमेल बनाकर जनहित में कार्य करने की अपेक्षा है।

भारत की टैरिफ कूटनीति के लाभ

चूंकि अब दुनिया में नए डिजिटल दौर की नई संपत्तियों से विकास की मंजिलें तय होंगी, अतएव ऐसी सबसे कीमती संपत्तियों के विकास पर भारत को ध्यान देना होगा। अब भारत में भारी पूंजी वाले उद्योगों को सबसिडी देने के बजाय शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक निवेश किया जाना अधिक लाभप्रद होगा। भारत को सेवा क्षेत्र की नई चमकीली राजधानी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना होगा...

अवकाश शर्मा

यकीनन इस समय टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और अमेरिका के लिए शुल्कों में कमी की रणनीति रंग लाते हुए दिखाई दे रही है। 9 अप्रैल को अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसे पहले देश के रूप में सामने आया है, जो अमेरिका के साथ सबसे पहले टैरिफ पर प्रभावी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की टैरिफ कूटनीति के लाभ उभरकर दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जहां अमेरिका के द्वारा चीन पर 145 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया गया है, वहीं अमेरिका पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाने वाले भारत सहित सभी देशों के लिए 90 दिनों तक टैरिफ के अमल को स्थगित कर दिया है। ट्रंप के इस निर्णय के बाद चीन ने अमेरिका पर 125 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। इससे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद भारतीय निर्यात पर मंडरा रही अनिश्चितता फिलहाल रुक गई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा विभिन्न देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाने के बाद नई व्यापार दुनिया ने जन्म ले लिया है। यह नई व्यापार दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप की उस हठ पर आधारित है जिसमें वे विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन और अमेरिका के साथ कथित आर्थिक दुर्व्यवहार को रोकने के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को होने वाले किसी भी तरह के कष्ट की अनदेखी करने को भी तैयार हैं।

नई व्यापार दुनिया पहले की व्यापार दुनिया से पूरी तरह से अलग है। कल तक दुनिया में मजबूत आर्थिक विश्व व्यवस्था और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के आधार पर विकास की कहानी आगे बढ़ती रही है, वहीं अब संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौतों का नया सितारा उदित

हो रहा है। ऐसे में भारत को अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों और दुनिया की बदलती आर्थिक सूरत की नई हकीकत के मद्देनजर नई रणनीति के साथ आगे बढऩा होगा। गौरतलब है कि ट्रंप के द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लागू किया गया है। ट्रंप का टैरिफ वियतनाम पर 46 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत तथा थाइलैंड पर 36 प्रतिशत सुनिश्चित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 फीसदी रही, जो करीब 77.5 अरब डॉलर थी, निर्यात की ऐसी ऊंचाई अमेरिका को भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाती है। ट्रंप के टैरिफ से भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इनमें आईटी, टेक्सटाइल और परिधान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद शामिल हैं। भारत के दवा और सेमीकंडक्टर उद्योग पर भी टैरिफ की तलवार लटक रही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 26 फीसदी पारस्परिक टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले से भारत के द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में करीब 5.76 अरब डॉलर की गिरावट आ सकती है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के करीब 0.2 फीसदी घटने की आशंका रहेगी। खास बात यह भी है कि ट्रंप के टैरिफ की आपदा के बीच भारत के लिए मौके भी छिपे हैं। जहां अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ दूसरे कई प्रतिस्पर्धी देशों से कम होने से अमेरिका सहित दुनिया में भारत के निर्यात बढऩे की संभावना है। भारत जिस तरह से अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते के लिए तथा अन्य देशों के साथ भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए रणनीतिपूर्वक कदम बढ़ा रहा है, उससे भारत के लिए अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात और कारोबार बढ़ाने के मौके भी बढ़ सकते हैं। चूंकि एशिया के उभरते बाजारों में भारत पर टैरिफ फिलीपींस को छोडकर सबसे कम है, ऐसे में तुलनात्मक रूप से कम टैरिफ से भारत को वैश्विक व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी।

प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देशों की तुलना में भारत पर कम टैरिफ लगा है। खास तौर पर चीन और वियतनाम के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति

में है। टेक्सटाइल के निर्यात बाजार में अभी से भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं। अन्य देशों के सामान अमेरिका में ज्यादा महंगे होने से अमेरिका में भी भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी। टैरिफ की चुनौतियों के बीच भी भारत की विकास दर बढऩे की संभावनाएं हैं। हाल ही में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ चुनौतियों के बीच भी चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहेगी और यह स्थिति अर्थव्यवस्था के मजबूत और स्थिर विस्तार का संकेत देती है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी। यद्यपि भारत में सरकार ने संसद में ट्रंप की नई टैरिफ नीति के मद्देनजर घरेलू उद्योगों के संरक्षण की बात कही है, लेकिन अब देश के उद्योग जगत के द्वारा टैरिफ संरक्षण की बजाय वैश्विक प्रतिस्पर्धा व अनुसंधान व विकास (आरएंडडी) पर ध्यान दिया जाना होगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वर्ष 1991 में उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ाने की जो रणनीति लागू हुई, उससे देश को उदारीकरण के लाभ मिले हैं। चूंकि टैरिफ प्रतिस्पर्धा से जुड़े हैं, अगर हम टैरिफ की आड़ में रहेंगे तो प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएंगे। नए अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को कारोबार करने में आसानी बढ़ानी होगी। लॉजिस्टिक्स व बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा और नीतिगत स्थिरता कायम रखनी होगी।

हम उम्मीद करें कि अमेरिका के द्वारा चीन पर लागू किए गए 145 फीसदी टैरिफ से शुरू हुए अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के बीच वैश्विक आर्थिक मौकों को मुठ्ठी में लेने के साथ-साथ भारत पर लागू किए जाने वाले 26 फीसदी टैरिफ की चुनौती का मुकाबला करने में भारत के लिए अमेरिका के साथ नया कारोबार समझौता, विभिन्न देशों के साथ नए द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौते और मजबूत घरेलू आर्थिक घटक असरकारक आर्थिक हथियार के रूप में उपयोगिता देते हुए दिखाई देंगे। हम उम्मीद करें कि सरकार नई व्यापार दुनिया में भारत को रचनात्मक देश बनाने के लिए ऐसी नई आर्थिक रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, जिसमें बड़े-बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म, छोटे और मझौले उद्योगों के लिए भी अनुकूलताएं हों। चूंकि अब दुनिया में नए डिजिटल दौर की नई संपत्तियों से विकास की मंजिलें तय होंगी, अतएव ऐसी सबसे कीमती संपत्तियों के विकास पर भारत को ध्यान देना होगा। अब भारत में भारी पूंजी वाले उद्योगों को सबसिडी देने के बजाय शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक निवेश किया जाना अधिक लाभप्रद होगा। भारत को सेवा क्षेत्र की नई चमकीली राजधानी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना होगा। साथ ही भारत को अधिक डिजिटल महारत हासिल करने पर ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से ऐसी नई आर्थिक और द्विपक्षीय वैश्विक व्यापार रणनीति से भारत नई व्यापार दुनिया के आकाश में एक चमकते हुए आर्थिक और प्रभावी सितारे के रूप में दिखाई दे सकेगा।

मुकुल शर्मा

शहरी विकास के लिए चेतावनी है यह भूकंप

वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक क्रियाओं के कारण भी भूकंप आते हैं। भूकंपों की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किमी भीतर होती है। इससे यह वैज्ञानिक धारणा भी बदल रही है कि भूकंप की विनाशकारी तरंगें जमीन से 30 किमी नीचे से चलती हैं...

म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के ताकतवर भूकंप ने 1700 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली और 2500 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप के प्रभाव में आकर जिस तरह से बहुमंजिला इमारतें ढहीं, सडकें, पुल और बांध टूटे, बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गईं, यह प्रकृति की एक ऐसी नजीर है, जो बढ़ते शहरीकरण के लिए चेतावनी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आए कुछ पलों के झटकों ने ही दुनिया के इस सुंदर शहर को थर्रा दिया। इसी बीच अमेरिका की भूगर्भीय सर्वेक्षण एजेंसी ने आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या 10 हजार से भी अधिक पहुंच सकती है। इस भूकंप के झटके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में भी अनुभव किए गए। चीन, वियतनाम, ताइवान, लाओस और श्रीलंका में भी भूकंप की तरंगें अनुभव की गईं। याद रहे भारत के भुज में 24 साल पहले आया भूकंप भी 7.7 तीव्रता का था, जिसमें 20 हजार लोगों की मौतें हुई थीं और डेढ़ लाख लोग घायल हुए थे। तीन लाख से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ था। म्यांमार का भूकंप काफी उथला था। इस भूकंप का केंद्र भूमि के 10 किमी नीचे था। भूकंप के केंद्र वाला म्यांमार का क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पूर्व से ही चिन्हित है। बावजूद यहां आवास और उद्योगों के लिए आलीशान अट्टालिकाएं खड़ी की जा रही हैं। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने का परिणाम इस भूकंप को माना जा रहा है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र में 17 फरवरी 2025 की सुबह 5.36 बजे रिक्टर स्केल पर चार तीव्रता वाले भूकंप के झटके और धमाकों जैसी अवाजें

सुनी गई थीं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र दिल्ली के धौलाकुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किमी की गहराई में था। इस कारण इसकी तीव्रता भूगर्भ में ही कमजोर पड़ गई और सतह पर नहीं आने पाई।

बिहार में भी भूकंप के झटके अनुभव किए गए। इसका केंद्र धरती की सतह से 10 किमी नीचे था। इसलिए असर केवल अनुभव हुआ। बावजूद भविष्य में भूकंप का यह संकेत दिल्ली के लिए विनाश की चेतावनी है। क्योंकि दिल्ली, हरिद्वार और महेंद्रगढ़, देहरादून के ऐसे पठारनुमा टीले पर बसा हुआ है, जहां से भूकंप की भ्रंश रेखा गुजरती है। अतएव यहां हमेशा भूकंप का खतरा बना रहता है। यह संकट इसलिए भी है क्योंकि यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र में भूमि की परत नरम है। हालांकि इस भूकंप को विवर्तनिक परत (टेक्टोनिक्स प्लेट) में किसी बदलाव के कारण आना नहीं माना गया था। इसके आने का कारण स्थानीय भूगर्भीय विविधता को माना जा रहा है। याद रहे हिमालय के उत्तरी तलहटी में स्थित चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र शिगात्से के निकट तिंगरी काउंटी में 7 जनवरी 2025 को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 126 लोग मारे गए थे। पड़ोसी देश नेपाल और भारत में भी इसके झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र तिंगरी काउंटी में था, जो हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट क्षेत्र का उत्तरी द्वार माना जाता है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने इस भूकंप की तीव्रता 7.1 आंकी थी। भूकंप से तिब्बत में किसी बांध या जालाशय को हानि नहीं पहुंची थी, गौरतलब है कि भूकंप ने भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना ने भारत और बांग्लादेश को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों में टकराव के कारण चीन के दक्षिण-पश्चिम हिस्से नेपाल और उत्तर-भारत में अकसर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप की चेतावनी संबंधी प्रणालियां अनेक देशों में संचालित हैं लेकिन वह भूगर्भ में हो रही दानवी हलचलों की सटीक जानकारी समय पूर्व देने में लगभग असमर्थ हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देने वाले अमेरिका, जापान, भारत, नेपाल, चीन और अन्य देशों में भूकंप आते ही रहते हैं, इसलिए यहां लाख टके का सवाल उठता है कि चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने का सपना और पाताल की गहराइयों को

नाप लेने का दावा करने वाले वैज्ञानिक आखिर पृथ्वी के नीचे उत्पात मचा रही हलचलों की जानकारी प्राप्त करने में क्यों असफल हैं, जबकि वैज्ञानिक इस दिशा में लंबे समय से कार्यरत हैं। अमेरिका एवं भारत समेत अनेक देश मौसम व भूगर्भीय हलचल की जानकारी देने वाले उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर चुके हैं।

दरअसल दुनिया के नामचीन विशेषज्ञों व पर्यावरणविदों की मानें तो सभी भूकंप प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि उन्हें विकराल बनाने में मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। इसीलिए इस भूकंप को स्थानीय भूगर्भीय विविधता का कारण माना गया है। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों के अकूत दोहन और फिर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए शैतानी निर्माण से छोटे स्तर के भूकंपों की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भविष्य में इन्हीं भूकंपों की व्यापकता और विकरालता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। पहले 13 सालों में एक बार भूकंप आने की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब यह घटकर 4 साल हो गई है। यही नहीं, आए भूकंपों का वैज्ञानिक आकलन करने से यह भी पता चला है कि भूकंपीय विस्फोट में जो ऊर्जा निकलती है, उसकी मात्रा भी पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हुई है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में जो भूकंप आया था, उनसे 20 थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बमों के बराबर ऊर्जा निकली थी। यहां हुआ प्रत्येक विस्फोट हिरोशिमा-नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। जापान और फिर क्वोटो में आए सिलसिलेवार भूकंपों से पता चला है कि धरती के गर्भ में अंगड़ाई ले रही भूकंपीय हलचलें महानगरीय आधुनिक विकास और आबादी के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रही हैं। ये हलचलें भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की धरती के नीचे भी अंगड़ाई ले रही हैं। इसलिए इन देशों के महानगर भूकंप के मुहाने पर खड़े हैं। भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया इस अभिशाप को झेलने के लिए जब-तब विवश होती रही है। बावजूद हैरानी इस बात पर है कि विज्ञान की आश्चर्यजनक तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक ईजाद करने में असफल रहे हैं, जिससे भूकंप की जानकारी आने से पहले मिल जाए। भूकंप के लिए जरूरी ऊर्जा के एकत्रित होने की प्रक्रिया को धरती की विभिन्न परतों के आपस में टकराने के सिद्धांत से आसानी से समझा जा सकता है। ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि करीब साढ़े पांच करोड़ साल पहले भारत और आस्ट्रेलिया को जोड़े रखने वाली भूगर्भीय परतें एक-दूसरे से अलग हो गईं और वे यूरेशिया परत से जा टकराईं।

इस टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आई और धरती की विभिन्न परतों के बीच वर्तमान में मौजूद दरारें बनीं। हिमालय पर्वत उस स्थल पर अब तक अटल खड़ा है, जहां पृथ्वी की दो अलग-अलग परतें परस्पर टकराकर एक-दूसरे के भीतर घुस गई थीं। परतों के टकराव की इस प्रक्रिया की वजह से हिमालय और उसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। इसी प्रायद्वीप में ज्यादातर एशियाई देश बसे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक क्रियाओं के कारण भी भूकंप आते हैं। भूकंपों की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किमी भीतर होती है। इससे यह वैज्ञानिक धारणा भी बदल रही है कि भूकंप की विनाशकारी तरंगें जमीन से कम से कम 30 किमी नीचे से चलती हैं। ये तरंगें जितनी कम गहराई से उठेंगी, उतनी तबाही भी ज्यादा होगी और भूकंप का प्रभाव भी कहीं अधिक बड़े क्षेत्र में दिखाई देगा। लगता है अब कम गहराई के भूकंपों का दौर चल पड़ा है। मैक्सिको में सितंबर 2017 में आया भूकंप धरती की सतह से महज 40 किमी नीचे से उठा था। इसलिए इसने भयंकर तबाही का तांडव रचा था। बहरहाल, अब सतर्क हो जाने का समय है।

वायुसेना की घटती ताकत पर सरकार करें विचार

भारत सरकार को कुछ अन्य सुरक्षा उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जिसमें हमारी हवाई रक्षा कवच (एयर डिफेंस) के साथ-साथ हमें ड्रोन और मिसाइल के एक एकीकृत बल के निर्माण को मजबूत बनाना होगा। उम्मीद है कि भारत सरकार चौतरफा चुनौतियों से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारियों को दुरुस्त बनाने के लिए आवश्यक निर्णयों को अमलीजामा पहनाएगी...

एन के शर्मा

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह वायुसेना में लड़ाकू विमानों के बेड़े की घटती ताकत को लेकर अपनी चिंताएं जगजाहिर कर चुके हैं। जिस प्रकार से वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लड़ाकू विमानों की आपूर्ति से जुड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं और इंजनों के लिए जनरल इलेक्ट्रिक पर निर्भरता कायम है, उसने भी भारतीय वायु सेना की ताकत और युद्ध के लिए तैयार रहने की कोशिशों को प्रभावित किया है। गत दिनों चाणक्य डायलॉग्स सम्मेलन में बोलते हुए वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत में हर साल कम से कम 35 से 40 सैन्य विमानों का निर्माण किए जाने की जरूरत है और यह क्षमता रातोंरात नहीं बनाई जा सकती है। 'भारत 2047 : युद्ध में आत्मनिर्भर' नामक विषय पर उन्होंने जोर देकर कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव भी नहीं है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अनुसार भारतीय वायुसेना 2047 तक अपनी सभी जरूरतों के सामान का उत्पादन भारत में ही करने की दिशा में काम कर रही है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 600 के करीब लड़ाकू विमान हैं, जिनमें 248 सुखोई 30 एमकेआई, 45 मिराज 2000, 130 जगुआर, 40 मिग 21 बाइसन, 32 तेजस एलसीए एमके 1, 65 मिग 29 और 36 राफेल शामिल हैं। लेकिन यदि चीन से तुलना की बात की जाए तो हमारे पास उसके विमानों के करीब आधी संख्या ही है।

भारतीय वायुसेना को अभी तक 40 स्वदेशी तेजस विमान भी नहीं मिले हैं जबकि चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी तैयार कर लिया है। 2008 में चीन का रक्षा बजट 78.78 अरब डॉलर का था, जो 2025 में भारत का रक्षा बजट है। यानी रक्षा बजट के मामले में हम आज भी चीन से 17 साल पीछे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक दशक तक रक्षा बजट को तुरंत जीडीपी के 4 प्रतिशत के बराबर किए जाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना के पास हर हाल में देश की सुरक्षा के लिए 42 स्क्वाड्रन का होना जरूरी है। लेकिन इस वक्त भारत के पास करीब 32 स्क्वाड्रन हैं और यदि स्क्वाड्रनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो साल 2035 तक भारत के पास सिर्फ 25 से 27 स्क्वाड्रन ही बचेंगे। इसलिए समझा जा सकता है कि आने वाले वर्षों में हालात किस कदर भयावह हो सकते हैं। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 लड़ाकू विमान होते

हैं। इस साल के अंत तक आखिरी मिग-21 को भी सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा। एचएएल को भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस एमआई1ए लड़ाकू विमान बनाने हैं और सभी 83 तेजस एमआई1ए की डिलीवरी साल 2029 तक देनी है, लेकिन इसमें भी देरी हो रही है। भारतीय वायु सेना की आधिकारिक स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी।

भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य 'नभः स्पृशं दीप्तम्' है। इसका मतलब है 'गौरव के साथ आकाश को छूना'। यह वाक्य भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय से लिया गया है। पिछले 93 वर्षों में भारतीय वायुसेना ने उपलब्धियों से परिपूर्ण एक गौरवशाली सफर तय किया है। भारतीय वायुसेना आसमान में भारत की ताकत को और बढ़ाना चाहती है और इसके लिए भारतीय वायुसेना को 114 नए लड़ाकू विमान चाहिए। मल्टी रोल फाइटर जेट प्रोग्राम के तहत ये विमान खरीदे जाने हैं। वायुसेना चाहती है कि 5 साल के भीतर पहला लड़ाकू विमान भारत में आ जाए।

खरीद प्रक्रिया में 7 विमान दौड़ में शामिल हैं। ज्यादातर विमानों का पहले ही परीक्षण हो चुका है, इसलिए उम्मीद है कि लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया तेज होगी। यह प्रसन्नता की बात है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन चुका है। ग्लोबल फायरपावर की तरफ से वर्ष 2025 की सैन्य ताकतों की रैंकिंग में पहले स्थान पर अमरीका है। दूसरे स्थान पर रूस का नंबर आता है, जबकि चीन तीसरे स्थान पर है। पांचवें स्थान पर दक्षिण कोरिया है। अपनी सैन्य व एटमी ताकत का धौंस देने वाला पाकिस्तान इस बार तीन अंक खिसक कर 12वें स्थान पर पहुंच चुका है। ग्लोबल फायर पावर नामक संस्था रैंकिंग के लिए 60 से ज्यादा मानकों पर ध्यान देती है। इसमें सेनाओं की संख्या, हथियारों की ताकत, लॉजिस्टिक्स लाने-ले जाने की क्षमता, भौगोलिक स्थिति शामिल हैं। फायरपावर इंडेक्स (जीएफपी) में कम स्कोर का मतलब देश की ज्यादा सैन्य ताकत होती है। अमरीका ने सबसे कम पावर इंडेक्स (0.744) हासिल कर टॉप किया है। भारतीय वायुसेना ने जिन युद्धों में भाग लिया है, उनमें द्वितीय विश्वयुद्ध, 1947 का भारत-पाक युद्ध, कांगो संकट, गोवा मुक्ति संग्राम, भारत-चीन युद्ध, 1965 का भारत-पाक युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पुमलाई, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल युद्ध आदि प्रमुख रहे हैं।

यह माना जाता है कि मशीन के पीछे खड़ा आदमी ही महत्वपूर्ण है, लिहाजा आज तक लड़ी गईं सभी मुख्य लड़ाइयों में भले ही वायुसेना के पास उन्नत श्रेणी के युद्धक विमान न रहे हों, लेकिन उनको संचालित करने वाले भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलेट अपने हौसलों से हर बार नया इतिहास रचते रहे हैं। भारत सरकार को कुछ अन्य सुरक्षा उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जिसमें हमारी हवाई रक्षा कवच (एयर डिफेंस) के साथ-साथ हमें ड्रोन और मिसाइल के एक एकीकृत बल के निर्माण को मजबूत बनाना होगा। उम्मीद है कि भारत सरकार चौतरफा चुनौतियों से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारियों को दुरुस्त बनाने के लिए आवश्यक निर्णयों को अमलीजामा पहनाने का कार्य यथाशीघ्र पूरा करेगी।

मुगलों को नाकों चने चबवाने वाला धर्म योद्धा वीर बन्दा सिंह बहादुर ही थे

सचिन तोमर

अपना सर्वस्व लुटा कर राष्ट्रधर्म कैसे निभाया जाता है। अपने गुरु के वचनों को सर्वोपरि कैसे माना जाता है और अपने दुश्मन की आँखों में आंखें डाल कर कैसे लडा जाता है। यह अगर किसी एक इंसान से सीखना हो तो केवल गुरु गोविंद सिंह जी के प्यारे शिष्य बंदा सिंह बहादुर है। कहते हैं कि योद्धा होने से पहले बंदा सिंह बहादुर एक वैरागी थे।

उनका पहला नाम माधो दास था उनको का जन्म 1670 ई. में कश्मीर स्थित पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में हुआ। कहते हैं कि वह महज 15 वर्ष के थे, जब उन्होंने एक मृग को अपनी आँखों के सामने प्राण त्यागते हुए देखा। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से विचलित कर दिया। इतना बिचलित कि उन्होंने वैराग्य धारण कर जानकीदास नामक वैरागी को अपना गुरु मान लिया। आगे के कुछ वर्ष जानकीदास के साथ रहने के बाद माधोदास वैरागी रामदास के सम्पर्क में आए तथा उनसे भी आध्यात्म के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसके पश्चात माधो दास ने योगसाधना सीखी तथा नांदेड क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। उधर दूसरी तरफ इस समयकाल में मुगलों के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। किन्तु माधोदास को इसकी कोई खबर नहीं थी। वह तो ज्यादातर समय अपनी योगसाधना में लगे रहते थे। इसी बीच अपने दो पुत्रों की शहादत और सिख कौम की सुरक्षा की चिंता से विचलिते गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ आना हुआ। स्थानीय लोगों द्वारा ने गुरु जी को माधो दास के बारे में बताया। स्थानीय लोग माधोदास से बहुत प्रभावित थे इसलिए गुरु जी ने उससे मिलने की इच्छा जताई।

माधोदस को देखते ही गुरु जी समझ गए कि

यह एक योद्धा है तथा इसका जन्म वैराग के लिए नहीं अपितु मजलूमों की रक्षा के लिए हुआ है। गुरु जी ने माधो दास को समझाते हुए कहा कि 'वीर योद्धा भी अगर वैराग धारण कर लेंगे फिर असहाय लोगों की रक्षा कौन करेगा ?'

गुरु जी के ज्ञान और उनके मासूम पुत्रों द्वारा जनहित में अपने प्राणों का बलिदान देने की कथा सुन कर माधोदास विचलित हो उठे तथा उन्होंने गुरु जी की बात मान कर शस्त्र उठाने का मन बना लिया। 3 सितंबर 1708 ई को गुरु गोविन्द सिंह जी ने माधोदास को अमृतपान कराने के बाद एक नया नाम दिया, जो था बंदा सिंह बहादुर।

गुरु जी का मार्गदर्शन मिलते ही बंदा सिंह की आँखें खुल गईं। उन्हें चारों ओर बेसहारा लोगों

की चीख पुकारें सुनाई देने लगीं। दो मासूम साहिबजादों की शहादत से विचलित मन उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। सन- 1709 ई में गुरु गोविन्द सिंह जी के आदेश पर बंदा सिंह बहादुर मुगलों से सिखों की रक्षा करने हेतु पंजाब के लिए निकल पड़े। यहाँ बंदा सिंह ने सिख सेना, मुगलों के आतंक से परेशान हिन्दुओं तथा आम जनता की मदद से मुगलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। समाना के युद्धे में बंदा सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने मुगलों के लगभग दस हजार सैनिकों को मार कर यह युद्ध जीत लिया।

इस जीत के बाद भले ही सिख सेना के हौंसले बुलंद थे मगर बंदा सिंह बहादुर का मन अभी तक विचलित था। उनके मन की आग अभी तक शांत नहीं हुई थी। इसका कारण था दो छोटे साहिबजादों के हत्यारे वजीर खान का अभी तक जीवित होना। अपने प्रतिशोध के लिए बंदा सिंह को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। 1710 ई में बंदा सिंह बहादुर के संरक्षण में सिख सेना ने सरहिंद पर चढ़ाई कर दी तथो चप्पर चिड़ी के युद्धे में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के फौजदार वजीर खान को मौत के घाट उतार दिया।

वजीर खाने की मृत्यु और सरहिंद पर कब्जा करने के साथ ही बंदा सिंह के संरक्षण में सिख साम्राज्य सतलुज से यमुना तक विस्तृत हो गया। बंदा सिंह ने मुखलिसगढ़ नामक एक गाँव बसाया और इसे अपनी राजधानी बना दिया। यहीं पर उन्होंने लोहगढ़ नामक किला भी बनवाया, जिसके कारण मुखलिसगढ़ को लौहगढ़ के नाम से जाना जाने लगा।

बंदा सिंह ने मुगलों की मुद्रा के स्थान पर सिख धर्म के सिक्के जारी करवा दिए। बंदा सिंह द्वारा सिख धर्म के नाम से पहली बार सिक्के चलाए गए थे। देखते ही देखते कुछ ही समय में बंदा सिंह ने पंजाब में अपना राज्य स्थापित कर लिया। अगली कड़ी में उन्होंने अपने साथियों को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दिया। यहाँ सिखों ने सहारनपुर, जलालाबाद, मुजफ्फरनगर और अन्य आस-पास के इलाकों पर कब्जा करने के साथ मुगलों द्वारा पीड़ित जनता को राहत पहुंचाई। इधर जालंधर और अमृतसर में सिखों ने असहाय लोगों के अधिकारों के लिए युद्ध शुरू कर दिए।

बंदा सिंह ने शासन सँभालते ही जमीदारी प्रथो को हटा कर किसानों को उनके हिस्से की जमीन लौटा दी। उनका मानना था कि इससे किसान सम्मान सहित अपना जीवन निर्वाह कर

पायेंगे। यही नहीं बंदा सिंह के शासन से पूर्व सभी वर्गों के अधिकारी जबरन वसूली तथा घुसखोरी के आदी हो चुके थे। साथ ही व्यवस्था के नियम और तरीके भी पूरी तरह से टूट चुके थे।

सिखों ने अपनी ताकत का सही प्रयोग करते हुए सभी भ्रष्ट अधिकारीयों को हटा कर उनके स्थान पर ईमानदारों को पदभार सौंप दिया। इस शासन व्यवस्था से आम जनता को बहुत राहत मिली। एक बार सदौरा से कुछ पीड़ित लोग अपने जमीदारों के खिलाफ शिकायत ले कर बंदा सिंह के पास आए।

पीड़ितों से उनकी फरियाद सुनने के बाद बंदा सिंह ने अपने सैनिक बाज सिंह को उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पीड़ित लोग अपनी फरियाद के बदले बंदा सिंह के ऐसे उत्तर से स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि बंदा सिंह मजलूमों की रक्षा करते हैं। उन्होंने बंदा सिंह से ऐसी प्रतिक्रिया का कारण पूछा तब बंदा सिंह ने उत्तर दिया कि 'आप सब हजारों की संख्या में होकर भी उन मुट्ठी भर जमीदारों के जुल्मों से बचने का उपाए नहीं ढूँढ पाए।' उसके बाद बंदा सिंह ने सदौरा के युद्धे में सैय्यदों और शेखों को पराजित किया तथा पीड़ितों को उनका अधिकार दिलवाया।

पूर्वी लाहौर से पूरे पंजाब पर सिखों के शासन ने मुगलों की राजधानी दिल्ली और लाहौर के बीच का संचार पूरी तरह बाधित कर दिया था। इस खबर ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को पूरी तरह से विचलित कर दिया। उसने पंजाब की ओर कूच कर दिया। बहादुर शाह ने बंदा सिंह को झुकाने के लिए पूरी शाही सेना को लगा दिया। सभी सेनापतियों को ये आदेश दिया गया कि वह शाही सेना में शामिल होकर उसकी ताकत को बढ़ाएं। बंदा बहादुर जिन दिनों उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थे... उन्हीं दिनों मुनिम खान के संरक्षण में मुगल सेना ने सरहिंद पर हमला कर दिया तथा सरहिंद सहित आस पास के इलाकों पर भी अपना कब्जा जमा लिया। बंदा सिंह जब वापिस आये तब उन्होंने अपनी सेना को अंतिम युद्ध के लिए लोहगढ़ में इकठ्ठा किया। इस युद्ध में सिख सेना ने मुगल सेना को हरा दिया। किन्तु, उन्होंने और सेना मंगवाई तथा 60 हजार सनिकों के साथ लौहगढ़ किले को घेर लिया। हालांकि बंदा सिंह यहाँ से बच निकलने में कामयाब रहे।

बाद में मार्च 1715 ई में मुगलों ने गुरदासपुर में स्थित गुरदास नंगल गाँव को चारों तरफ से घेर लिया। यह वही जगह थी, जहां बंदा सिंह अपने साथियों के साथ रुके हुए थे। एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः मुगल बंदा सिंह को पकड़ने में कामयाब रहे। दिल्ली ले जाते समय बंदा सिंह को लोहे के पिंजरे में कैद किया गया। दूसरी तरफ बाकी सिखों को जंजीरों से बाँधा गया था। दोबारा कोई बंदा सिंह के रास्ते पर न चल सके। इसके लिए मुगलों ने सिखों को अमानवीय यातनाएं तक दीं। सभी सिखों के दिल्ली पहुँचने पर उन्हें प्राणदान देने के बदले अपना धर्म छोड़ने के लिए दबाब बनाया गया। यही नहीं बंदा सिंह बहादुर के सामने ही उनके सात वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गयी। अंत में मुगलों ने सारी हदें पार कर दी और बंदा सिंह की आँखें फोड़कर गर्म सलाखों द्वारा उनके शारीर की त्वचा खींच ली गयी। इतनी असहनीय पीड़ा के बाद भी बंदा सिंह ने दुश्मनों के आगे सिर नहीं झुकाया और मृत्यु को प्यारे हो गये।

असहाय लोगों के अधिकार तथा अपने लोगों की रक्षा के लिए अंतिम साँस तक सीना तान कर दुश्मनों के सामने खड़े रहने वाले बंदा सिंह बहादुर से आने वाली पीढियां प्रेरणा लेती रहेगी।

अखिलेश के रूख से पार्टी की हिन्दू लॉबी एवं पिछड़े मुसलमानों में नाराजगी

कपिल चौहान

मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को कानून बनाकर एक नया इतिहास लिख दिया है। इन संशोधनों को 'उम्मीद' का नाम दिया गया है,लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनैतिक दलों के साथ-साथ समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिये मोदी सरकार द्वारा लाये गये वक्फ संशोधन का खुलकर विरोध किया,लेकिन मुस्लिम राजनीति को करीब से जानने वाले कुछ लोगों को लग रहा है कि इससे सपा को फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मुस्लिमों में कई पिछड़ी बिरादरियां इस बिल का समर्थन भी कर रही हैं। इसमें ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल, जमीयत हिमायत उल इस्लाम और पसमांदा मुस्लिम महाज जैसे मुस्लिम संगठन शामिल हैं,जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है. इन संस्थाओं ने वक्फ बोर्डों पर इतने सालों से काबिज रहे लोगों से तीखे सवाल पूछे हैं. इन संगठनों का दावा है कि वक्फ बिल पास होने से सिर्फ वो मुसलमान परेशान हैं जो खुद वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर कब्जा किए बेठे हैं.पसमांदा (पिछड़े) मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह संगठन वक्फ बिल के पक्ष में है. सितंबर 2024 में जेपीसी की बैठक में इसने बिल को 85 प्रतिशत मुस्लिमों के लिए फायदेमंद बताया था। इस संगठन का कहना है कि यह बिल वक्फ बोर्ड में सुधार लाकर हाशिए पर पड़े मुस्लिमों को लाभ पहुंचाएगा,लेकिन यह बात समाजवादी पार्टी जैसे दलों के नेताओं को समझ में नही आ रही है।

यही वजह है लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिल के विरोध में अपने मुस्लिम सांसदों की 'फौज' उतार दी। आजमगढ़ के सांसद धमेन्द्र यादव,संभल के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क,कैराना की सासंद इकरा हसन चौधरी,गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी,रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने बिल के विरोध में मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, तो राज्यसभा में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बिल के विरोध में मोर्चा संभाला। इनमें से एक मुस्लिम सांसद ने तो चर्चा के दौरान धमकी भरी आवाज में यहां तक कह दिया कि मुसलमान इस कानून को नहीं मानेंगे। सपा की सांसद इकरा चौधरी ने बहस के दौरान झूठा आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ईद पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। समाजवादी पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जिन सांसदों को बोलने का मौका दिया था,उसमें या तो यादव कुनबे से जुड़े सांसद थे या फिर मुस्लिम सांसद। सपा की तरफ से सात सांसदों ने अपनी बात विस्तार से रखी जिसमें चार मुसलमान सांसद थे और तीन मुलायम कुनबे के सांसद। समाजवादी पार्टी ने अपने 37 सांसदों में से जिन सांसदों को बहस के लिये चुना उसमें एक भी यादव कुनबे से इत्तर या फिर गैर मुस्लिम सांसद नहीं था। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी को शक की नजर से देखा जा रहा है। सपा के हिन्दू सांसदों के बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। पार्टी के बेइंतहा मुस्लिम प्रेम के चलते हिन्दू बाहुल्य लोकसभा सीटों से चुनाव जीतने वाले हिन्दू सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गये हैं। इस बात का अहसास तब और मजबूत हो गया जब वक्फ बिल पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम परस्त रवैये के बीच अयोध्या लोकसभा चुनाव सीट से जीतने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद अचानक रामलला के दर्शन करने पहुंच गए,जबकि अभी तक अखिलेश अपने इस सांसद को पार्टी का मुखौटा बनाये घूम रहे थे। अवधेश चुनाव जीतने के 11 महीने बाद रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यह तब हुआ जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 'इशारे' पर अभी तक अवधेश प्रसाद रामलला के मंदिर जाने से बचते रहे थे,लेकिन अब उन्हें भी लगने लगा है कि यदि उनकी भी छवि मुस्लिम परस्त बन गई तो हिन्दू बाहुल्य रामलला की नगरी में आगे सियासत करना उनके लिए आसान नहीं होगी।यही स्थिति समाजवादी पार्टी के अन्य उन सांसदों की भी है जो 2024 के आम चुनाव में हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव जीत कर आये थे इसी के चलते इन सांसदों का वक्फ बिल के समर्थन में कोई बयान भी नहीं आया है।

बात इससे आगे की कि जाये तो समाजवादी पार्टी ने खासकर उन सांसदों को बिल का विरोध करने का मौका दिया जिनकी छवि पहले से ही काफी विवादित है और इन सांसदों की पहचान हिंदुओं और उनके देवी देवताओं को अपमानित करने वाली रही हैं। एक-एक कर इन सांसदों की बात की जाये तो संभल के सांसद जिया-उर-रहमान के दिवंगत सांसद पिता अक्सर हिन्दुओं के खिलाफ जहर उगला करते थे। उन्हीं की तर्ज पर जिया उर रहमान बर्क चल रहे हैं। नवंबर 2024 में संभल की शाही मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। इस घटना के बाद, पुलिस ने सपा सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ उपद्रव की साजिश रचने

का मुकदमा दर्ज किया था। बर्क पर बिजली चोरी और संभल हिंसा के दौरान एक वर्ग विशेष के लोगों को भड़काने का भी आरोप है। इसी तरह से कैराना की सपा सांसद इकरा हसन चौधरी भले ही सांसद हों,लेकिन उनकी स्वयं की पृष्ठभूमि कोई राजनैतिक नहीं है। समाजवादी पार्टी कैराना की सांसद इकरा हसन के भाई, नाहिद हसन, का विवादों से गहरा नाता रहा है। वह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनके खिलाफ लगभग डेढ़ दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप भी शामिल हैं. नाहिद की दबंगई के कारण कई हिन्दू परिवार कैराना से पलायन को मजबूर हो गये थे। जनवरी 2022 में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, नाहिद हसन को शामली में गिरफ्तार किया गया था। जिस कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाये, इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनकी बहन इकरा हसन को कैराना सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करा दिया। आज इकरा भाई की सोच को ही आगे बढ़ा रही हैं।

समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी भी वक्फ बिल के दौरान मोदी सरकार पर खूब बरसे थे,अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। गाजीपुर के आसपास मुख्तार की तूती बोलती थी,कहा यह जाता था कि मुख्तार के पास मसल पॉवर थी तो इसके पीछे दिमाग अफजाल अंसारी का रहता था। समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने 12 फरवरी 2025 को शादियाबाद में संत रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में महाकुंभ स्नान पर विवादित टिप्पणी की। इससे पहले भी उन्होंने साधु-संतों और धार्मिक प्रथाओं पर टिप्पणियां की थी, जिनसे विवाद उत्पन्न हुआ था। मुख्तार अंसारी की मौत के समय अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जिलाधिकारी से भी अभद्रता करते देखा गया था।

समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी भी वक्फ बिल के खिलाफ खूब दहाड़े थे,नदवी को अखिलेश ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की इच्छा के खिलाफ लोकसभा का टिकट दिया था। नदवी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान में जेल में बंद आजम का बिना नाम लिये कहा था कि जेल सुधार गृह होती है। जिससे पार्टी के भीतर तनाव बढ़ा। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने नदवी के इस बयान की आलोचना की। इन घटनाओं से समाजवादी पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद और रामपुर की राजनीति में तनाव स्पष्ट होता है। नदवी का पारिवारिक जीवन भी विवादों से भरा है। नदवी का अपनी एक बीवी से तलाक का मुकदमा चल रहा है,उसे वह कोर्ट के आदेश के बाद भी गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं।

समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल पर चर्चा के लिये जिन सांसदों को आगे किया,उसके चलते ही सपा पर आरोप लग रहा है कि अब उसके आइडियल मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम,दारा शिकोह, कृष्ण भक्त रसखान,वीर अब्दुल हमीद(परमवीर चक्र विजेता), बिस्मिल्लाह खां (शहनाई वादक), डॉ. अब्दुल कलीम अजीज (इतिहासकार), अब्दुल कय्यूम अंसारी (स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता), शाह मुबारक अली (शिक्षाविद और समाज सुधारक), जोहरा सहगल (अभिनेत्री और नृत्यांगना), कैप्टन अब्बास अली (स्वतंत्रता सेनानी) जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे। आजादी के बाद समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे। पर इन हस्तियों के नाम पर समाजवादी पार्टी में कोई चर्चा नहीं होती है। बल्कि बाबर, औरंगजेब, बाहुबली अतीक अंसारी,मुख्तार अंसारी,यासीन मलिक,दाऊद,याकूब मैनन,अफजल गुरू जैसे विवादित लोग सपा में सिरमौर है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की साजिश रची जाती है।

अराजकता में डूबा बंगाल

ARD

मुर्शिदाबाद हिंसा के जरिए पूरे बंगाल में हिंसा फैलाने का प्लान तुर्की में बनाया गया था, इसके जरिए बंगाल के हालात भी ठीक बांग्लादेश की तरह करने की कोशिश थी। हिंसा को लेकर बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई थी कि कौन कहां नुकसान करेगा और लूटपाट मचाएगा।

वक्फ कानून को लेकर बढ़ती हिंसा

बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा का सिलसिला जिस तरह तेज और सांप्रदायिक होता जा रहा है, जिस तरह से हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मुर्शिदाबाद से पलायन को विवश किया जा रहा है, वह मुस्लिम तुष्टीकरण और दुष्प्रचार की खतरनाक राजनीति का प्रतिफल तो है ही, वह कुशासन एवं अराजकता की भी चरम पराकाष्ठा भी है। नए वक्फ कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को विशेषतः किशोर बच्चों को हिंसा एवं तोड़फोड के लिये जानबूझकर सड़कों पर उतारने में लगे हुए हैं। वे उन्हें अराजकता एवं उन्माद के लिए उकसा भी रहे हैं और तरह-तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं। अराजकता फैलाने वाले किस तरह बेखौफ हैं, इसकी पुष्टि इससे होती है कि वे सरकारी-गैरसरकारी वाहनों को तोड़ने, जलाने के साथ पुलिस पर भी हमले कर रहे हैं। बंगाल के विभिन्न जिलों में वक्फ कानून के विरोध के बहाने फैलाई जा रही अराजकता इसलिए भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ खड़ी होकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा का बढ़ना, हिन्दुओं में डर पैदा होना, भय का वातावरण बनना, आम जनजीवन का अनहोनी होने की आशंकाओं से घिरा होना चिंताजनक भी है और राष्ट्रीय शर्म का विषय भी है।

यह बंगाल पुलिस के नाकारापन एवं ममता सरकार के मुस्लिम तुष्टिकरण का ही दुष्परिणाम है कि मुर्शिदाबाद के साथ ही अन्य शहरों में भी वक्फ कानून के विरोध की आड़ में हिंसा, तोड़फोड, आगजनी हो रही है। खतरनाक यह है कि इस दौरान हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वक्फ कानून विरोधियों की अराजकता से उपजे हालात का संज्ञान लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इससे शर्मनाक एवं दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता कि मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू पलायन कर गए हैं। हिंदू परिवारों का आरोप है कि हिंसा के दौरान उनको चुन-चुनकर निशाना बनाया गया। उनके पीने के पानी में जहर तक मिला दिया गया है। इस हिंसा की जांच एजेंसियों ने पोल खोल दी है, यह हिंसा पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी, जिसमें तुर्की से फंडिंग और स्थानीय मदरसों की मिलीभगत सामने आई है। हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई और इनाम की व्यवस्था भी की गई थी। ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार देश में एकमात्र ऐसी सत्तारुढ़ पार्टी एवं नेता बन गई है जिसका देश के संविधान, न्यायपालिका एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं रह गया है।

वक्फ कानून का विरोध करने सड़क पर उतरे तत्वों के दुस्साहस का पता इससे चलता है कि वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे हैं। उनके इसी दुस्साहस के चलते मुर्शिदाबाद के हिंदुओं ने खुद को असहाय पाया। बंगाल में कानून के शासन ने सुनियोजित हिंसा के दुष्चक्र के समक्ष एक बार फिर समर्पण कर दिया। बंगाल में इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। मई 2021 में विधानसभा चुनावों के बाद वहां तृणमूल समर्थक तत्वों ने अपने राजनीतिक विरोधियों को इतना आतंकित किया था कि वे जान

बचाने के लिए असम में शरण लेने को मजबूर हुए थे। तब भी वहां पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। ताजा हिंसक हालातों में राज्य सरकार और उसके नेता यह झूठ देश के गले में उतारने में लगे हुए हैं कि बंगाल में स्थितियां नियंत्रण में हैं। यह कैसा नियंत्रण है? यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा दोगलापन है? जिसमें एक समुदाय खुलेआम दूसरे समुदाय को निशाना बना रहा है। खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर राष्ट्र-विरोधी विचारों का जहर घोला जा रहा है।

वक्फ कानून में संशोधन का विरोध विडम्बनापूर्ण होने के साथ देश में अराजकता फैलाने का माध्यम बना हुआ है। वक्फ कानून में संशोधन के तहत किसी मस्जिद, मदरसे आदि को लेकर किसी भी तरह के नुकसान, कब्जा करने या दखल की बात नहीं कही गयी है। इसके विरोधी चाहे जो तर्क दें, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए थे और सरकारी-निजी जमीनों पर मनमाने तरीके से दावा कर दिया करते थे। उनकी इस मनमानी का शिकार अनेक मुस्लिम भी थे। क्या वक्फ कानून के विरोधी यह बताने की स्थिति में हैं कि वक्फ बोर्डों ने अभी तक कितने गरीब मुसलमानों की सहायता की? यह पहली बार नहीं है, जब किसी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उपद्रव, हिंसा, आगजनी की जा रही हो। इसके पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी ऐसा ही किया गया था। तब यह झूठ फैलाया जा रहा था कि इस कानून के जरिये मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। अब यह झूठ फैलाया जा रहा है कि नए वक्फ कानून के जरिये सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। यह निरा झूठ और शरारत ही है। वक्फ कानून के विरोधी भले ही लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हों, लेकिन ये उसकी धज्जियां ही उड़ा रहे हैं। वे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं।

मुर्शिदाबाद हिंसा के जरिए पूरे बंगाल में हिंसा फैलाने का प्लान तुर्की में बनाया गया था, इसके जरिए बंगाल के हालात भी ठीक बांग्लादेश की तरह करने की कोशिश थी। हिंसा को लेकर बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई थी कि कौन कहां नुकसान करेगा और लूटपाट मचाएगा। इसके साथ ही इनाम देने को लेकर योजनाएं बनाई गयी। हिंसा के दौरान इस बात का खास ध्यान देने का अलर्ट किया गया कि रेल और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट न चल पाए। मौका मिलने पर हिंदुओं की हत्या करना भी टारगेट था। कुछ हिन्दुओं को मारा भी गया है। हिंदुओं के घरों के साथ मंदिरों पर हमले किए गए, घर जलाए गए, आजीविका नष्ट की गई, बलात्कार की धमकियां दी गयी, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले न केवल सांप्रदायिक घृणा में डूबे हैं, अराजकता एवं उन्माद पर सवार है, आतंकी माहौल बनाकर हिन्दुओं को भयभीय-आतंकित करना चाहते है। क्योंकि उन्हें यह भरोसा है कि ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाली। ज्यादा चिन्ताजनक तो यह है कि अराजक लोग चाहते हैं पलायन करने के लिए मजबूर लोग फिर कभी अपने घरों को न लौट पाएं। इन जटिल एवं अनियंत्रित होते अराजक हालातों में शांति, सौहार्द एवं सामान्य हालातों को निर्मित करने के लिये आवश्यक है कि केंद्र सरकार बंगाल में हस्तक्षेप करने के लिए आगे आए, बल्कि यह भी अपेक्षित है कि सुप्रीम कोर्ट वहां के हालात का स्वतः संज्ञान ले। उसे वक्फ कानून विरोधी हिंसक तत्वों के उपद्रव के लिए ममता सरकार को जवाबदेह बनाना ही होगा।

ममता वोट बैंक की राजनीति के लिये कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां बार-बार उड़ाती रही है। ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया है, कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। ममता अपने बलबूते चुनाव जीतने का माद्दा रखती है तो फिर हिंसा का सहारा क्यों लेती है? अराजकता फैलाकर अपने ही शासन को क्यों दागदार बनाती है? क्यों अपने प्रांत की जनता को डराती है, भयभीत करती है? क्या ये प्रश्न ममता की राजनीतिक छवि पर दाग नहीं है? ममता एवं तृणमूल कांग्रेस का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। ताजा हिंसक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। राज्य में शीर्ष संवैधानिक पद पर रहते हुए भी ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक, गैर-कानूनी एवं राष्ट्र-विरोधी कार्यों को अंजाम दिया है। बंगाल में तो भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के जबड़े फैलाए, हिंसा की जीभ निकाले, मगरमच्छ सब कुछ निगल रहा है। ममता अपनी जातियों, ग्रुपों और वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं-- देश को नहीं।

वक्फ संशोधन कानूनः भड़काई गई सुनियोजित हिंसा से यदि नहीं चेते तो अंजाम और भी बुरे होंगे!

मनोज शर्मा

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़काई गई सुनियोजित हिंसा से यदि हमारा प्रशासन समय रहते ही नहीं चेता तो आने वाले दिनों में अंजाम और भी बुरे होंगे, इतिहास इसी बात की चुगली कर रहा है! यह नसीहत क्रूर वक्त हमें बार-बार दे रहा है, लेकिन हमलोग ऐसे घिसे पिटे आदर्शवादी हैं कि उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं इसलिए आज मैं इतिहास की अंगड़ाई में सुलगते हुए वर्तमान के कुछ कटु सत्य को उद्घाटित कर रहा हूँ ताकि हमारे राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की कुम्भकर्णी निंद्रा टूटे और वो विधि-व्यवस्था के लिहाज से अपने मौलिक कर्तव्य न भूलें।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन पहले मुस्लिम आक्रान्ताओं ने और फिर ब्रिटिश नौकरशाहों ने अपने-अपने प्रशासनिक स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी-ऐसी अव्यवहारिक नीतियों को कानूनी अमली जामा पहनाया, जिससे हिन्दू समाज जाति और क्षेत्र के नाम पर बिखर गया और कभी मुस्लिम अधिकारी तो कभी ईसाई अधिकारी और उनके पिट्ठू लोग हिन्दुओं पर हावी होते चले गए। इसी कड़ी में सांप्रदायिक, जातीय और क्षेत्रीय हिंसा को अघोषित प्रशासनिक एजेंडे के तौर पर बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा, कभी प्रशासनिक उदासीनता तो कभी पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाते हुए संगठित अपराध को बढ़ावा दिया गया, जिससे विधि व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चली गई।

इसी स्थिति से निजात पाने के लिए देश में आजादी की लड़ाई तेज हुई और साम्पदायिक विभाजन तक की नौबत आई इस दौरान हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी खूब हुए। लेकिन भारत के गाँधी-नेहरु जैसे अव्यवहारिक आदर्शवादी राजनेताओं ने आजाद भारत में हालत बदलने के उलट उन्हीं घिसे-पिटे कानूनों को भारतीयों पर थोप दिया, जो आज तक अशांति का सबब बन चुकी हैं। पहले कांग्रेसियों, फिर समाजवादियों और अब राष्ट्रवादियों ने ढोंगी धर्मनिरपेक्षता की तो खूब बातें कीं, लेकिन अपने कुत्सित जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक एजेंडे से आगे की कभी नहीं सोच पाए।

मसलन, बहुमत की आड़ में शांतिप्रिय सत्ता परिवर्तन भी सुनिश्चित हुआ, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका और समाजपालिका से जुड़े लोग मुगलिया और ब्रितानी प्रशासनिक लापरवाहियों से कोई सबक नहीं सीख पाए। सबों ने उस 'निर्जीव भारतीय संविधान' का महिमा मंडन किया और कर रहे हैं जिसने पदासीन लोगों को वेतन-भत्ते-पेंशन और देशवासियों से लूट-खसोट की तो गारंटी दी, लेकिन आमलोगों के सुख-शांति में खलल डालने वालों के खिलाफ कभी सख्ती नहीं दिखाई। इस नजरिए से संसद और विधान मंडलों ने प्रभावकारी कानून नहीं बनाए और न ही न्यायपालिका ने इस प्रशासनिक प्रवृति पर कभी सवाल उठाए। हद तो यह कि न्याय के नाम पर मामलों को वर्षों तक लटकाने वाली न्यायपालिका, नेताओं के इशारों पर उलटे-सीधे कार्य करने की अभ्यस्त हो चली कार्यपालिका और नेताओं-कारोबारियों की अघोषित सांठगांठ से जहाँ सत्ताधारी जमात मौज में रहता आया है, वहीं आम आदमी सुपोषण योग्य भोजन, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सुविधा, जन-सुरक्षा के लिए मोहताज है। एक ओर देश के अमनपसंद आमलोग जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्मान की प्राप्ति के लिए आरक्षण को अचूक हथियार समझ बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर 1947 में पाकिस्तान और 1972 में बंगलादेश लेने वालों के वंशज ब्रेक के बाद भारतीय भूभाग पर सांप्रदायिक तांडव मचा रहे हैं और नेताओं की नीतिगत लापरवाहियों से हमारा सिविल और पुलिस प्रशासन असहाय बना रहता है।

हैरत की बात है कि कभी ये लोग दलित-मुस्लिम समीकरण तैयार करवाते हैं तो कभी मुस्लिम-ओबीसी समीकरण को फंडिंग करवाते हैं। वहीं इसी की आड़ में अभिजात्य मुसलमान विदेशों से हवाला के जरिए फंडिंग लेकर देश में पाकिस्तान-बांग्लादेश के ही नहीं बल्कि अरब देशों के हमदर्द पैदा करते हैं। इनकी नापाक मंशा जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे हालत पूरे देश में पैदा करने की है, जिसकी झलक गाहे-बगाहे दिखाते रहते हैं। यदि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत तक के ब्रेक के बाद होने वाले सांप्रदायिक दंगों की बात छोड़ भी दी जाए तो अयोध्या रामजन्म भूमि आंदोलन, फिर सीएए और अब वक्फ कानून की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर या फिर चीन-अमेरिका-

इंग्लैंड से शह प्राप्त अन्य मुस्लिम देशों के इशारे पर भारत में जो अशांति फैलाते हैं, इसका ताजातरीन उदाहरण पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाका है, जो इन दिनों इस्लामिक उत्पात से जल रहा है।

दरअसल वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़क उठी है, उससे केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाओं की आशंका जताई है। इसके दृष्टिगत वह लगातार सतर्कता बरत रही है। यह बात दीगर है कि अभी तक अन्य राज्यों से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की अधिसूचना के मद्देनजर अभी तक अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से किसी भी सांप्रदायिक स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई जोखिम नहीं उठा रहा है। केंद्र बंगाल के साथ-साथ अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, जहां वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों की खबरें आई हैं। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी कारक की पहचान करना और संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें शुरू में ही समाप्त कर दिया जाए।

बताया जाता है कि यदि राज्यों से मांग की जाती है, तो उन्हें बिना किसी देरी के केंद्रीय बल मुहैया कराए जाएंगे, ताकि ऐसी सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सके। इसी उद्देश्य से मुर्शिदाबाद में भी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अदालत के निर्देश पर पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, जिससे सांप्रदायिक झड़पों पर लगाम लगी। अधिकारी ने कहा कि वहां अब कोई नई हिंसा नहीं हुई है। गत शनिवार को मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्थिति का आकलन किया। इसके साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार की। दरअसल डीजीपी ने केन्द्रीय गृह सचिव को जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है और स्थानीय स्तर पर तैनात बीएसएफ कर्मियों की मदद ली जा रही है। वहीं सांप्रदायिक हिंसा में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में शनिवार को 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद में स्थानीय स्तर पर मौजूद करीब 300 बीएसएफ कर्मियों के अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर पांच अतिरिक्त कंपनियां वहां भेजी गई हैं।

पूरे देश में लागू हुआ नया वक्फ कानून केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन

वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे देश में आज से यानी 8 अप्रैल से लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। इसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार को भी सुना जाए। भारत सरकार के कानूनी दस्तावेजों में से एक, भारत का राजपत्र है। इसमें सरकार के सभी आदेश और सूचनाएं प्रकाशित होती हैं।

वक्फ कानून को लेकर केंद्र ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'केंद्र सरकार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की उप-धारा (2) की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 अप्रैल, 2025 को वह तारीख नियुक्त करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।'

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दाखिल किया कैविएट

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया है। कैविएट एक तरह की अर्जी होती है। इसे कोई भी पक्ष हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी आदेश बिना उसे सुने पारित न किया जाए। केंद्र सरकार ने यह कैविएट वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ दाखिल किया है।

5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने दी थी नए वक्फ कानून को मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी थी। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद पारित किया गया था। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने वक्फ विधेयक के पक्ष में और 95 सदस्यों ने विरोध में वोट दिया। वहीं लोकसभा में 288 सदस्यों ने इसे समर्थन दिया जबकि 232 ने विरोध में मतदान किया।

क्या अबकी बार बंगाल बोलेगा 'जय श्रीराम' या फिर 'खेला होबे'

बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और इस बार इसकी जड़ में है भगवान राम का नाम, जिसकी आस्था को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी चुनावी रणनीति के रूप में चुन लिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी तनाव गहराता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी का पर्व अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया, बल्कि यह राज्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला एक अहम मौका बन गया है। रामनवमी के दिन जिस तरह बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने राज्य भर में तकरीबन 2000 शोभा यात्राएं निकालीं, उसने यह साफ कर दिया कि पार्टी 2026 के चुनाव में किस एजेंडे के साथ मैदान में उतरेगी। इन यात्राओं में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, हाथों में भगवा झंडे, तलवारें, जय श्रीराम के नारे और भगवा वस्त्रों में लिपटे कार्यकताओं की भीड़ ने यह संदेश दे दिया कि यह आस्था की

हरेन्द्र शर्मा

नहीं, सियासत की भी यात्रा है।

बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल और शुभेंदु अधिकारी जैसे वरिष्ठ नेता इन आयोजनों का चेहरा बने, जिन्होंने मंच से सीधे-सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अग्निमित्रा पॉल ने यहां तक कहा कि राम शोभा यात्रा के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, केवल पुलिस को सूचित करना होता है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में राम मंदिर की आधारशिला रखकर ममता बनर्जी को सीधे उनके गढ़ में चुनौती दी। नंदीग्राम वही इलाका है जहां 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन ने ममता को सत्ता की ओर पहला बड़ा मौका दिया था और अब वही स्थान बीजेपी की रणनीति का आधार बन गया है।

बीजेपी इस बार किसी भ्रम में नहीं है। पार्टी को पता है कि पश्चिम बंगाल में उसने पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर अपनी सबसे बड़ी सफलता दर्ज की थी और अब वह उस आधार को और मजबूत करना चाहती है। 2016 के चुनाव में जहां बीजेपी को केवल 10.2% वोट मिले थे, वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 38.1% तक पहुंच गया था। यह उछाल केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श का संकेत है, जिसे बीजेपी और आरएसएस बखूबी भुनाना चाह रहे हैं। इसीलिए अब पार्टी ने हिंदुत्व को चुनावी हथियार के रूप में और भी धारदार बना दिया है।

रामनवमी की इन शोभा यात्राओं के पीछे केवल धार्मिक उत्साह नहीं था। यह सांस्कृतिक दावे और राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की एक योजनाबद्ध

कोशिश थी। बंगाल के विभिन्न जिलों में जो यात्राएं निकाली गईं, उसमें भगवा रंग की स्पष्टता, जय श्रीराम के नारों की गूंज और हिंदू धर्म के प्रतीकों की भरमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी अब बंगाल को भी उसी तरह हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाहती है, जैसा वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में कर चुकी है। पार्टी यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि बंगाल की धरती भी राम की है, यहां भी उनके भक्तों की संख्या कम नहीं है और वे अब राजनीतिक बदलाव की तैयारी में हैं।

बीजेपी की इस रणनीति के जवाब में ममता बनर्जी ने भी चुप्पी साधे रखने का रास्ता नहीं चुना। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बंगाल की संस्कृति को बाहरी तत्वों से खतरा है। उन्होंने दोहराया कि बंगाल, गुजरात या यूपी नहीं है। यहां की संस्कृति, भाषा, खानपान और जीवनशैली अलग है और उसे किसी बाहर से आई विचारधारा से बदलने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में भी इसी 'बाहरी बनाम बंगाली' नैरेटिव के सहारे बीजेपी को घेरने में कामयाबी पाई थी और अब वह उसी पथ को फिर से अपनाने जा रही हैं। बंगाली अस्मिता की बात कर ममता फिर से राज्य की जनता को यह संदेश देना चाहती हैं कि बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति इस राज्य की मिट्टी से मेल नहीं खाती। तृणमूल कांग्रेस इस बार न सिर्फ अस्मिता की बात करेगी बल्कि ममता की प्रशासनिक ताकत को भी सामने रखेगी। रामनवमी के दौरान किसी भी बड़े हिंसक घटना का न होना, पुलिस की मौजूदगी और शांति बनाए रखना, यह सब ममता सरकार की ओर से एक संदेश है कि वह हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रख सकती हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने खुद कहा कि पिछले दो महीने से शोभा यात्राओं को लेकर पुलिस बल की तैयारी की जा रही थी और इसी वजह से किसी तरह की बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। ममता इसे अपनी सफलता के रूप में प्रचारित करेंगी और इसे बीजेपी की अराजकता के खिलाफ एक मजबूत प्रशासनिक प्रतिवाद के रूप में दिखाएंगी।

बीजेपी की रणनीति के तहत अब बंगाल के उन स्थानों को भी धार्मिक नक्शे में प्रमुखता से रखा जा रहा है, जिनका रामायण काल से कोई न कोई संबंध माना जाता है। बर्दवान का सुश्रवणगढ़, बांकुड़ा का गंधेश्वरी मंदिर और बीरभूम का गिरिधारीपुर जैसे स्थानों को राम या हनुमान से जोड़ते हुए एक नया धार्मिक विमर्श रचा जा रहा है। यह कोशिश बंगाल की मिट्टी को राममय करने की है, जिससे जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और भगवान राम में कोई विरोध नहीं है। बीजेपी के लिए यह सांस्कृतिक पुनःस्थापना का अवसर है और वह इसमें कोई चूक नहीं करना चाहती। लेकिन यह लड़ाई केवल धार्मिक प्रतीकों तक सीमित नहीं रहेगी। टीएमसी के रणनीतिकार जानते हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता को केवल अस्मिता की राजनीति से रोका नहीं जा सकता, इसके लिए जमीनी मुद्दों पर भी काम करना होगा। इसलिए ममता बनर्जी का जोर विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी रहेगा। महिला मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ पहले से ही मजबूत है और वह इसे और भी मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही ममता यह भी चाहेंगी कि मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ एकजुट रहें, जैसा उन्होंने 2021 में किया था।

भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर हिन्दुत्व की राजनीति कर रही है। उसके सामने यह मजबूरी नहीं है कि हिन्दू वोटरों को खुश करने के चक्कर में उनके हाथों से मुस्लिम वोटर निकल सकते हैं। क्योंकि बीजेपी को मुस्लिमों का साथ कभी मिलता ही नहीं है। वहीं ममता बनर्जी एक तरफ मुस्लिम वोटों को कांग्रेस या वामपंथी दलों पाले में जाने से बचाने में लगी हैं। वहीं हिन्दुओं को भी नाराज नहीं करना चाहती हैं। यही दुविधा ममता बनर्जी पर भारी पड़ रही है। राहुल गांधी आजकल पश्चिम बंगाल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनका ज्यादा फोकस मुस्लिम वोटरों पर है, इसको लेकर भी ममता बेचैन हैं।

कांग्रेस यदि बंगाल में ठीकठाक लड़ती है तो इससे ममता बनर्जी की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है ?वहीं बीजेपी मुस्लिम वोटों के बंटने पर फायदे में रहेगी बीजेपी का सियासी हमला हालांकि तीव्र है, लेकिन ममता की सरकार भी जवाब देने में उतनी ही तेज नजर आ रही है। राज्य में प्रशासनिक मजबूती, सांस्कृतिक गर्व और विकास के मिश्रण से वह यह संदेश देना चाहती हैं कि बंगाल की राजनीति का चेहरा बीजेपी नहीं, बल्कि तृणमूल ही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी हर धार्मिक पर्व, हर सांस्कृतिक अवसर को एक चुनावी मंच की तरह इस्तेमाल कर रही है। रामनवमी इसके लिए पहला पड़ाव था, आने वाले महीनों में दुर्गा पूजा, दीवाली, और अन्य त्योहारों को भी राजनीतिक रंग दिए जाने की पूरी संभावना है।

2026 का चुनाव अब केवल एक राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गया, यह विचारधाराओं की जंग बन चुका है। एक ओर है राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश, दूसरी ओर है बंगाली अस्मिता की रक्षा की हुंकार। यह संघर्ष अब चुनावी मैदान तक सिमटा नहीं रहेगा, बल्कि हर गली, हर चौक, हर मंदिर, हर कॉलेज और हर पंचायत में महसूस किया जाएगा। जनता को अब तय करना है कि वे किस रास्ते पर जाना चाहते हैं राम के नाम पर भगवा राजनीति या ममता की नीली-हरी अस्मिता। यह फैसला केवल बंगाल की दिशा नहीं तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करेगा।

राजनीति के इस रामायण में हर दल अपने-अपने पात्रों को सजाने में जुटा है, लेकिन अंत में जनता ही है जो राम की भूमिका निभाएगी और सत्ता की संजीवनी किसे देनी है, यह फैसला करेगी। इतिहास गवाह है कि बंगाल कभी किसी के लिए आसान नहीं रहा और इस बार की जंग तो और भी पेचीदा और दिलचस्प होने जा रही है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा, यह संघर्ष और भी उग्र होगा और शायद इस बार राजनीति का असली चेहरा बंगाल से ही सामने आएगा।

सभी बड़े फैसले में अमित शाह ही फोकस में क्यों ?

'बिगत कुछ समय में देखें तो यह साफ दिख जायेगा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन हो या फिर संसद के बाहर सभी बड़े फैसले गृहमंत्री अमित शाह को ही आगे करके कर रहे हैं..चाहे वह नया नवेला वक्फ कानून हो या फिर पहले का तीन तलाक, यूसीसी, एनआरसी, 370धारा, .. वो सारे मुददे जो हिन्दुत्व या फिर राष्ट्रवादी हो सभी पर अमित शाह ही फोकस में होते हैं..क्या यह संयोग है या फिर कोई प्रयोगङ्क वैसे मोदी जी के विकल्प की चर्चा जोर पकड़ रही है तो कहीं उसी दिशा में बांकियो से आगे निकलने की होड़ तो नहीं है'...

यह अनजाने में नहीं हुआ कि इस बार संसद के बजट सत्र में पूरा फोकस अमित शाह के ऊपर रहा है और सत्र के बाद भी अमित शाह राजनीति करने और प्रशासन संभालते दिख रहे हैं। वैचारिक मुद्दों से जुड़े जो भी मुद्दे भारत के विशाल हिंदू मध्यवर्ग के मन में हैं उनका समाधन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। यह पूरा काम योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है और इसका मकसद उत्तर मोदी काल यानी पोस्ट मोदी एरा के लिए भाजपा का नेतृत्व तैयार करना है। कई जानकार यह मान रहे हैं कि अगर यथास्थिति रहती है यानी सब कुछ अभी जैसा चल रहा है वैसे चलता रहा तो पोस्ट मोदी एरा में देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी होंगे। भाजपा की ओर से कोई भी चेहरा अखिल भारतीय स्तर पर उनके मुकाबले का नहीं दिख रहा है। तभी अमित शाह की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता को उभारने और उसके प्रचार की रणनीति पर काम हो रहा है।

इस रणनीति की एक झलक वक्फ संशोधन बिल पर संसद में हुई चर्चा में दिखी। संसद के दोनों सदनों में बिल पास कराने और विपक्ष का जवाब देने का जिम्मा अमित शाह ने संभाल रखा था। बिल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू का था लेकिन उस पर सबसे ज्यादा अमित शाह बोले। इस बिल का प्रशासनिक मकसद जो भी रहा हो लेकिन राजनीतिक मकसद यह है कि हिंदुओं में यह मैसेज जाए कि भाजपा की सरकार है तो मुस्लिमों को सुधारा जा रहा है। तीन तलाक के फैसले से यही मैसेज गया था। लेकिन तब यह कहा गया था कि मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को राहत दिलाई है। इस बार अमित शाह के वक्फ बोर्ड कानून बना कर मुस्लिम संगठनों को ठीक करने मैसेज दिया गया है। तभी प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बिल के दौरान संसद में नहीं गए।

वे बिम्सटेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को बैंकॉक गए। लोकसभा में बुधवार को जब बिल पेश हुआ तो वे दिल्ली में थे लेकिन सदन में नहीं गए। इतना ही नहीं उनके बाद भाजपा के दोनों बड़े नेता राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी इस बिल पर नहीं बोले। जब अमित शाह बोल रहे थे तब अगली बेंच पर वे अकेले थे। उस बेंच पर मोदी, राजनाथ और गडकरी तीनों बैठते हैं लेकिन तीनों सदन में

नहीं थे। वक्फ बिल का पूरा क्रेडिट शाह को जाने दिया गया।

इसके बाद संसद का सत्र खत्म होते ही अमित शाह छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने नक्सलियों से एक भावुक अपील करते हुए कहा कि कोई भी नक्सली मारा जाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता इसलिए उनको हथियार छोड़ कर मुख्यधारा में लौट आना चाहिए। लेकिन साथ ही यह संकल्प भी दोहराया कि अगले साल चैत्र नवरात्रि तक नक्सलवाद का नामोनिशान मिट जाएगा। वक्फ और मुस्लिम की तरह नक्सलवाद और अरबन नक्सल भी मध्य वर्ग की एक ग्रंथि है। दंतेवाड़ा से लौट कर अमित शाह तीन दिन के लिए जम्मू कश्मीर गए। वहां उन्होंने सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया और विकास के कामों को लेकर बैठक की। ध्यान रहे कश्मीर भी भारत के लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। सो, तमाम भावनात्मक और वैचारिक मुद्दे अब अमित शाह हैंडल कर रहे हैं।

'वक्फ की संपत्ति के रखरखाव के लिए बिल', लोकसभा में बोले अमित शाह, वोट बैंक के लिए भ्रम फैला रहा विपक्ष

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड में किसी गैर-मुस्लिम की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग अपने मिथकों से देश को तोड़ देंगे। यह विधेयक वक्फ बोर्ड में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मैं अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं दोपहर 12 बजे से चल रही चर्चा को ध्यान से सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कई सदस्यों के बीच कई गलतफहमियां हैं, चाहे वह वास्तविक हो या राजनीतिक। साथ ही, इस सदन के माध्यम से उन गलतफहमियों को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ अधिनियम और बोर्ड 1995 में लागू हुआ। गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में सभी तर्क वक्फ में हस्तक्षेप के बारे में हैं। सबसे पहले, कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ में नहीं आ सकता। इसे अच्छी तरह से समझ लें।

अमित शाह ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में किसी गैर-मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, हम ऐसा नहीं करना चाहते। यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि यह कानून मुसलमानों के धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप करेगा और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा। यह भ्रांति अल्पसंख्यकों में अपने वोट बैंक के लिए डर पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है। शाह ने कहा कि वक्फ बिल मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है।

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड में किसी गैर-मुस्लिम की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग अपने मिथकों से देश को तोड़ देंगे। यह विधेयक वक्फ बोर्ड में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। अगर 2013 में संशोधन लाया गया होता, तो मैं कह सकता हूं कि आपको विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्था है। 2014 के नतीजों से डरकर उन्होंने ये संशोधन नहीं लाए, बल्कि इसे अतिवादी बना दिया।

शाह ने सवाल किया कि गैर-मुस्लिम सदस्य कहां शामिल होंगे? काउंसिल और वक्फ बोर्ड में। वे क्या करेंगे? वे कोई धार्मिक गतिविधि नहीं चलाएंगे। वे केवल वक्फ कानून के तहत किसी व्यक्ति द्वारा दान की गई संपत्ति के प्रशासन की देखभाल करेंगे, चाहे वह कानून के अनुसार हो रहा हो, चाहे संपत्ति का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो जिसके लिए उसे दान किया गया था। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 के चुनावों से ठीक पहले नई दिल्ली में 123 वीआईपी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दान कर दी थीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन करके रेलवे की जमीन भी वक्फ को दान कर दी थी। उन्होंने कहा कि वक्फ परिषद और बोर्डों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का शोषण करने वालों को पकड़ना होगा।

देश को बांटने के लिए भाजपा ने पेश किया वक्फ बिल: ममता

बनर्जी ने एक बयान में भाजपा की उसके विभाजनकारी एजेंडे के लिए आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे सांसद वक्फ मुद्दे पर बोलने के लिए दिल्ली में हैं। 'जुमला पार्टी' का केवल एक ही एजेंडा है - देश को बांटना। वे 'फूट डालो और राज करो' में विश्वास करते हैं।'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने देश को बांटने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा नीत सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो (इस) वक्फ विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन किया जाएगा। बनर्जी ने बुधवार को एक बयान में भाजपा की उसके विभाजनकारी एजेंडे के लिए आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे सांसद वक्फ मुद्दे पर बोलने के लिए दिल्ली में हैं। 'जुमला पार्टी' का केवल एक ही एजेंडा है - देश को बांटना। वे 'फूट डालो और राज करो' में विश्वास करते हैं।' ममता बनर्जी ने रामनवमी की योजना पर भी भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'केंद्र ने गरीबों के लिए सभी काम बंद कर दिए हैं। फिर केंद्र सरकार क्यों है? क्या यह एक नया धर्म शुरू करने के लिए है जिसमें रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और हमारे वेद शामिल नहीं हैं? क्या यह लोगों, देश को विभाजित करने और दंगे भड़काने के लिए है?' उन्होंने लोगों से आग्रह किया, 'मैं सभी धर्मों से आग्रह कर रही हूं। अपने त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। दंगा न करें और दंगा भड़काने की कोशिश भी न करें। आप दंगा भड़काने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम कार्रवाई करेंगे।' ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के मुख्यालय नबान्न में एक सम्मेलन आयोजित किया। वहां उन्होंने कहा, 'मैं इसका कड़ा विरोध करती हूं। मैं (केंद्र से) इस फैसले को वापस लेने का अनुरोध करती हूं। मैं आम

लोगों से विरोध करने का आग्रह करूंगी। अन्यथा केंद्र का यह एकतरफा फैसला स्वास्थ्य पर भारी पड़ेगा।' इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, 'अपनी 'जुमलेबाजी' को रोकने के लिए केंद्र सरकार को और कितने पैसे की जरूरत है। लोगों को अपने मेडिक्लेम में जीएसटी क्यों देना पड़ रहा है। गरीब लोग कहां जाएं। हम दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं पार्टी के सांसदों से भी इसका विरोध करने का अनुरोध करती हूं। वे आज वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार हमारे संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। वे हमारे देश को बांटना चाहते हैं।'

वक्फ कानून को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार से की ये खास अपील

मायावती ने कहा कि भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों को अपने राजनीतिक हितों को छोड़कर भारतीय कानून के तहत आतंकवादियों के खिलाफ निष्पक्ष और ईमानदार सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम को शामिल करने का प्रावधान गलत प्रतीत होता है, तथा मुस्लिम समुदाय भी इस पर आपत्ति जता रहा है। बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम पर पुनर्विचार करे तथा उसे निलंबित कर दे ताकि अन्य समान विवादास्पद प्रावधानों में सुधार हो सके। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों को अपने राजनीतिक हितों को छोड़कर भारतीय कानून के तहत आतंकवादियों के खिलाफ निष्पक्ष और ईमानदार सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले मायावती ने एक्स पोस्ट में कहा था कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद, निष्कार्ष यही निकलता है कि केन्द्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी सन्देहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता।

उन्होंने आगे लिखा था कि लेकिन दुःख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। वहीं, मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर छलावापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मायावती ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन में खासकर भाजपा के 'छद्म राष्ट्रवाद' व दलित एवं पिछड़े बहुजन-हित आदि को लेकर प्रस्ताव छलावा व अविश्वसनीयता से ग्रस्त हैं।

जबरदस्ती पारित किया वक्फ विधेयक, यह संविधान पर खुला हमला: सोनिया गांधी

सोनिया गांधी नेआरोप लगाया कि चाहे वह शिक्षा हो, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता हो, हमारा संघीय ढांचा हो या चुनाव का संचालन हो, मोदी सरकार देश को रसातल में धकेल रही है, जहां हमारा संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा और हम जानते हैं कि उनका इरादा उसे भी ध्वस्त करने का है।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक को संविधान पर बेशर्म हमला करार देते हुए कहा कि यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में रखने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। लोकसभा द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पारित किए जाने के कुछ घंटों बाद गांधी ने कहा कि निचले सदन में इस विधेयक को 'बुलडोजर' से पारित कर दिया गया। यहां संविधान सदन में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक संविधान का एक और उल्लंघन है और पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी।

सोनिया गांधी नेआरोप लगाया कि चाहे वह शिक्षा हो, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता हो, हमारा संघीय ढांचा हो या चुनाव का संचालन हो, मोदी सरकार देश को रसातल में धकेल रही है, जहां हमारा संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा और हम जानते हैं कि उनका इरादा उसे भी ध्वस्त करने का है। गांधी ने बैठक में सांसदों से कहा, ₹हम सभी के लिए यह जरूरी है कि हम सही और न्यायसंगत के लिए लड़ते रहें, मोदी सरकार की विफलता और भारत को निगरानी राज्य में बदलने के इरादे को उजागर करें। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सभी पार्टी सांसद मौजूद थे।

सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 2004-2014 के दौरान की गई कई पहलों को अपनी निजी उपलब्धियों के रूप में पुनः ब्रांड किया, पुनः पैकेज किया और विपणन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे भी हमारी अपनी सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से उजागर करने की आवश्यकता है। संसद के दोनों सदनों के कामकाज पर बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं है और सत्ता पक्ष अक्सर कांग्रेस को अपने मुद्दे उठाने की अनुमति न देने के लिए व्यवधान पैदा करता हुआ पाया जाता है।

वक्फ बिल अपनी विफलताओं को छिपाने का एक तरीका है: अखिलेश

अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा की हार होगी। भाजपा पीडीए की एकता का सामना नहीं कर सकती। इसके अलावा, समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि सरकार प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती है और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हर निर्णय ले रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून भाजपा की नाकामियों को छिपाने का एक तरीका है, जिसे उनकी योजनाओं की नाकामियों को छिपाने के लिए लाया गया है। जौनपुर में मीडिया से बात करते हुए यादव ने कहा कि वक्फ बिल उनकी नाकामियों को छिपाने का एक तरीका है। वे अपनी योजनाओं की नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे कानून लाए हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी इसे स्वीकार नहीं किया।

अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा की हार होगी। भाजपा पीडीए की एकता का सामना नहीं कर सकती। इसके अलावा, समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि सरकार प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती है और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हर निर्णय ले रही है। अखिलेश यादव ने कहा, 'वे महंगाई पर जवाब नहीं देना चाहते हैं और बेरोजगारी दर में काफी वृद्धि हुई है। वे जवाब नहीं देना चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। सरकार कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हर निर्णय ले रही है।' सपा प्रमुख ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता। वह कह रहे हैं कि तीन साल में वह गरीबी मिटा देंगे, यानी गरीबी शून्य हो जाएगी। वे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की 'बेतुकी' प्रथा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस तरह की प्रथा को गलत, बेतुका और शीर्ष अदालत द्वारा पहले के फैसले में जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत बताया। इसने स्पष्ट किया कि पैसा लेना और वापस न करना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है।

बच्चों को बचपन से सिखाएं अच्छी आदतें

यह हर माता पिता का दायित्व है कि बच्चों को पालना और अच्छी आदतें सिखाएं। बच्चे अपनी साथी बच्चों व बड़ों से कैसे बोलते हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये संस्कार बच्चों में अपने माता पिता से ही आते हैं। बच्चे यदि जिद्दी हैं और वे अपनी भाषा में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए अभिभावक ही सीधे तौर ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए यदि आपके बच्चे छोटे हैं कि उन्हे संस्कार जरुर सिखाएं।

बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी मां-बाप की होती है। बच्चों को बुरे संस्कारों से बचाने में पिता के मुकाबले मा की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को कब क्या सिखाना है और खिलाना है, इसकी सीधी-सीधी जिम्मेदारी मां की होती है। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से कुछ आदतें सिखानी जरुरी होती है।

यह आदतों एक से दो साल के बच्चे को सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। एक से दो साल के बच्चे को देर तक बैठाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उसके पास किसी टॉय को भी रखें। बच्चे को फिर अभिवादन करना सिखाएं। उसे मम्मी, पापा, बाबा, दादा, मामा आदि शब्दों का सही तरह से बोलना सिखाएं।

तीन से छह साल का बच्चा कुछ समझदार सा हो जाता है। इसलिए उससे थोड़ा प्यार से काम लेना चाहिए। इस उम्र के बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते-कूदते हैं और घर के बाहर उनके दोस्त बनाते हैं। इसलिए इस आयु के बच्चों को अपने खिलौने शेयर करना सिखाएं। साथ ही उसे सिखाएं कि वह खेलते समय अपने दोस्तों को से लड़ाई न करे और न ही किसी से झूठ बोले। दोस्त या पड़ोस में अपने घर से बाहर जाने पर बच्चे को गुड बाय और थैंक्यू बोलना सिखाएं।

सात से दस साल के बच्चे को सही और गलत की पहचान करने की समझ विकसित हो जानी चाहिए। आप अपने बच्चे को बतायें कि उसे यदि अपने जन्मदिन पर कोई तोहफा मिले, तो उसे धन्यवाद अवश्य लिखें। इस उम्र के बच्चों को अपने दोस्तों के साथ किस तरह खेलना है और कैसे एक-दूसरे की सलाह को मानना है, ये सब आपको बताना चाहिए।

आपको चाहिए कि अपने बच्चे को सिखाएं कि उसे अपने से बड़ों के साथ किस तरह सभ्यता से पेश आना चाहिए। उन्हें तमीज से बात करनी चाहिए और जो उनसे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पेश आना है। बच्चों को स्कूल में अपना टिफिन व पुस्तकें, पाठ्य सामग्री को शेयरिंग की सीख दें। उन्हें यह भी बताएं कि वे अपने खास दोस्तों से ही स्कूल में लंच, किताबें और खिलौने वगैरह शेयर करें।

आध्यात्म का जन्म और मृत्यु से सम्बन्ध नहीं

आध्यात्मिक प्रक्रिया जीवन और मृत्यु के बारे में नहीं होती। शरीर का जन्म व मृत्यु होती है, जबकि आध्यात्मिक प्रक्रिया आपके बारे में होती है, जो कि न तो जीवन है और न ही मृत्यु। अगर इसे आसान शब्दों में कहा जाए तो इस पूरी आध्यात्मिकता का मकसद उस चीज को हासिल करने की कोशिश है, जिसे यह धरती आपसे वापस नहीं ले सकती। आपका यह शरीर इस धरती से लिया गया कर्ज है, जिसे यह धरती पूरा का पूरा आपसे वापस ले लेगी। लेकिन जब तक आपके पास यह शरीर है, तब आप इससे ऐसी चीज बना सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, जो धरती आपसे वापस न ले पाए। चाहे आप प्राणायाम करें या ध्यान, आपकी ये सारी कोशिशें आपकी जीवन ऊर्जा को एक तरह से रूपांतरित करने का तरीका हैं, ताकि ये मांस बनाने के बजाय कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व का निर्माण कर सके, जो मांस की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ हो। अगर आप इस सूक्ष्म तत्व को पाने की कोशिश नहीं करेंगे तो जीवन के अंत में जब आपसे कर्ज वसूली करने वाले आएंगे तो वे आपसे सब चीज ले लेंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद की आपकी यात्रा का हिस्सा अच्छा नहीं होगा।

गुफाओं में जाकर धरती से सम्बन्ध बनाने का महत्व

इस शरीर को अपने बारे में बहुत गुमान होता है, लेकिन आप इस धरती का महज एक छोटा सा हिस्सा हैं। इसलिए हम लोग शरीर को ज्यादा से ज्यादा धरती के संपर्क में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे उसको लगातार इस बात का अहसास होता रहे कि वह इसी धरती का एक छोटा सा हिस्सा है। यही वजह है कि आध्यात्मिक लोग हमेशा नंगे पैर रहते हैं और खाली जमीन पर बैठना पसंद करते हैं। जमीन पर पालथी मारकर बैठने से शरीर को कहीं न कहीं इस बात का अनुभव होता है। जिस क्षण यह धरती के संपर्क में आता है, इसे तुरंत अहसास हो जाता है कि यह भी धरती ही है। यही वजह है कि ज्यादातर आध्यात्मिक लोग पहाड़ों में जाना व रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में याद दिलाने का यह काम ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है। पहाड़ वो जगह है, जहां धरती आपसे मिलने के लिए ऊपर उठी हुई है। अगर आप आप पहाड़ों में बनी गुफा में चले जाएं तो आपको अपने चारों तरफ धरती का अहसास होगा। यह अपने आप में याद दिलाने का एक जबरदस्त तरीका है। इसलिए पहाड़ों में रहना चुनौतीपूर्ण होते हुए भी योगी अक्सर अपने रहने के लिए पहाड़ों को चुनते हैं। वहां शरीर को लगातार याद दिलाया जाता रहता है, मन या बुद्धि को नहीं, कि वह नश्वर है।

हाथों और पैरों से मिट्टी को छूना मदद करता है

जब आप लगातार इस बात को महसूस करते हैं कि आप नश्वर हैं, तो आपके शरीर को भी हर वक्त इस बात अहसास रहता है कि वह यहां स्थायी नहीं है। तब आपकी आध्यात्मिकता स्थिर हो जाती है। आश्रम में मैं एक बात हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप चाहें जो भी काम कर रहे हों, लेकिन दिन में कम से कम एक घंटा आप अपने हाथों से जमीन में कुछ काम जरूर करें। भले ही आप बगीचे में कुछ करें, नहीं तो कुछ देर नंगे पैर चलें। यह आपमें एक तरह से शारीरिक याद्दाश्त भरेगा कि आप नश्वर हैं। अपने आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शरीर में इस बात का लगातार अहसास होना बेहद जरूरी है। यह जितनी जल्दी होगा, आपके भीतर आध्यात्मिकता का भाव उतना ही मजबूत होगा।

बेहाल वृद्धों के लिये आयोग बनना एक सराहनीय कदम

मुकुल पंडित

केरल योजना बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिणी राज्य पूरे भारत की तुलना में अधिक तेजी से वृद्ध हो रहा है। 1961 में, केरल में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 5.1 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत 5.6 प्रतिशत से थोड़ा कम थी।

केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने के लिए एक कानून पारित किया है। यह एक सराहनीय एवं स्वागत योग्य पहल होने के बावजूद एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर भारत के बुजुर्ग इतने उपेक्षित एवं प्रताड़ित क्यों है? केरल जैसे शिक्षित राज्य में ही इस आयोग को बनाने की जरूरत क्यों सामने आयी?

केरल में क्यों सामाजिक सुरक्षा, स्नेह, सुरक्षा की वह छांव लुप्त होती जा रही है, जिसमें बुजुर्ग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। क्यों केरल में ही बुजुर्ग सर्वाधिक अकेलेपन एवं एकाकीपन का संत्रास झेलने को विवश हो रहे है? केरल में कई बुजुर्ग लोगों को युवा पीढ़ी के हाथों गरीबी और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रांत में कई गांव ऐसे हैं जहां केवल बुजुर्ग ही बचे हैं, प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है? यूं तो समूचे देश में बुजुर्गों की लगभग यही स्थिति बन रही है, जो सामाजिक व्यवस्था पर एक बदनुमा दाग है।

केरल योजना बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिणी राज्य पूरे भारत की तुलना में अधिक तेजी से वृद्ध हो रहा है। 1961 में, केरल में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 5.1 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत 5.6 प्रतिशत से थोड़ा कम थी। हालांकि, 1980 के दशक तक, राज्य ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया। 2001 तक यह हिस्सा बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.5 प्रतिशत था। 2011 में यह 12.6 प्रतिशत था, जबकि राष्ट्रीय औसत 8.6 प्रतिशत था। केरल के योजना बोर्ड के अनुसार, 2015 में यह बढ़कर 13.1 प्रतिशत हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 8.3 प्रतिशत था। अब, दक्षिणी राज्य में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 4.8 मिलियन लोग हैं। इसके अलावा, बुजुर्ग समूह का 15 प्रतिशत 80 वर्ष से अधिक आयु का है, जो इसे बुजुर्ग लोगों के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाला आयु समूह बनाता है। 60 से अधिक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है और उनमें से अधिकांश विधवाएं हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को पारित इस कानून की सराहना करते हुए कहा कि यह नया आयोग बुजुर्गों के अधिकारों, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा।

देश में बुजुर्गों की हालत दिन-ब-दिन जटिल होती जा रही है। केरल देश के सबसे शिक्षित राज्यों में शुमार होता है तो बुजुर्गों के प्रति बरती जा रही

उपेक्षा, उदासीनता एवं प्रताड़ना में भी सबसे आगे है। लगभग 94 फीसदी साक्षरता वाले इस राज्य में बुजुर्ग शिक्षित युवाओं के पलायन का संत्रास झेल रहे हैं। राज्य के करीब 21 लाख घरों में युवाओं के पलायन करने के कारण सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं। गांव के गांव पलायन का दंश झेलते हुए वीरान हो चुके हैं। लाखों घरों में सिर्फ ताले लटके नजर आते हैं। खाड़ी के देशों में जाकर सुनहरा भविष्य तलाशने की होड़ में इसी प्रांत के सर्वाधिक युवा है। भले ही इस प्रांत ने सर्वाधिक शिक्षा से प्रगतिशील सोच दी है, लेकिन अंतहीन भौतिक लिप्साओं को भी जगाया है, जिससे ही बुजुर्गों की उपेक्षा या उनको उनके हाल पर छोड़ देने की विकृत मानसिकता एवं त्रासदी उभरी है। वृद्धों की उपेक्षा देशभर में देखने को मिल रही है, हाल के वर्षों में केरल के बाद पंजाब-हरियाणा में भी नजर आ रही है। वैसे तो यह हमारे नीति-नियंताओं की नाकामी का भी परिणाम है कि हम युवाओं को उनकी योग्यता-आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार देश में नहीं दे पाए। उन्हें न अपनी जन्मभूमि का सम्मोहन रोकता है और न ही यह फिक्र कि उनके जाने के बाद बुजुर्ग माता-पिता का क्या होगा? एकाकीपन का त्रास झेलते केरल के इन गांवों में बुजुर्गों के पास पैसा तो है मगर समाधान नहीं है। कुछ वृद्धों के पास तो धन का अभाव भी इस समस्या को विकराल रूप दे रहा है। राज्य में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही बुजुर्गों के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं।

भारत में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा एवं उदासीनता एक बढ़ती चिंता का विषय है, उनका एकाकीपन एवं अकेलापन उससे बड़ी समस्या है। केरल के वृद्ध-संकट को महसूस करते हुए वहां की सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया है, जो एक सूझबूझभरा कदम है। लेकिन यह वक्त बताएगा कि भ्रष्ट अफसरशाही व घुन लगी व्यवस्था में ये आयोग कितना कारगर होगा? लेकिन फिर भी जिस राज्य में हर पांचवें घर से एक व्यक्ति विदेश चला गया है, वहां ऐसा आयोग एक सीमा तक तो समस्या के समाधान की दिशा में रोशनी बनेगा। जरूरत है सरकारी अधिकारी संवेदनशीलता एवं इंसानियत से बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान करने के लिये आगे आये। केरल की सामाजिक न्याय मंत्री आर. बिंदु के अनुसार आयोग समृद्ध और निम्न आय वाले दोनों ही परिवारों के वृद्ध व्यक्तियों के शोषण की समस्या का महत्वपूर्ण समाधान करेगा। जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, उनकी गरिमा, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ लोगों को अक्सर स्वास्थ्य में गिरावट, अकेलेपन और वित्तीय असुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आवश्यक सहायता प्रदान करने से अधिक समावेशी और दयालु समाज बनाने में मदद मिलती है।

निस्संदेह, बुजुर्गों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर करना है। बेहतर चिकित्सा सेवा व घर-घर उपचार की सहज उपलब्धता समस्या का समाधान दे सकती है। वैसे अकेले रह रहे बुजुर्गों को भी इस दिशा में पहल करनी होगी। सामाजिक सक्रियता एवं मनोबल इसमें सहायक बनेगा। नीति-नियंताओं को सोचना होगा कि अगले दशकों में देश युवा भारत से बुजुर्गों का भारत बनने वाला है। वर्ष 2050 तक भारत में साठ साल से अधिक उम्र के 34.7 करोड़ बुजुर्ग होंगे। क्या इस चुनौती से निपटने को हम तैयार हैं? क्या केरल की तरह अन्य राज्यों की सरकारें एवं केन्द्र सरकार लगातार बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं के लिये ठोस कदम उठायेगी? वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करने वाला देश एवं उसकी नवपीढ़ी आज एक व्यक्ति, एक परिवार यानी एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, वे अपने निकटतम परिजनों एवं माता-पिता को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गतदिनों हाईकोर्ट के अनेक फैसलों को पलटते हुए सराहनीय पहल की है। जिनमें अब बुजुर्ग माता-पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम कराने या फिर उनसे गिफ्ट हासिल करने के बाद उन्हें यूं ही छोड़ देने, वृद्धाश्रम के हवाले कर देने, उनके जीवनयापन में सहयोगी न बनने की बढ़ती सोच पर विराम लगेगा, क्योंकि यह आधुनिक समाज का एक विकृत चेहरा है।

संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने वृद्धों के जीवन को नरक बनाया है। बच्चे अपने माता-पिता के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते। ऐसे बच्चों के लिए सावधान होने का वक्त आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला में कहा है कि अगर बच्चे माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं, तो माता-पिता की ओर से बच्चों के नाम पर की गई संपत्ति की गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। यह फैसला माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दिया गया है, जिससे वृद्धों की उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार के इस गलत प्रवाह को रोकने में सहयोग मिलेगा। नये विश्व की उन्नत एवं आदर्श संरचना बिना वृद्धों की सम्मानजनक स्थिति के संभव नहीं है। वर्किंग बहुओं के ताने, बच्चों को टहलाने-घुमाने की जिम्मेदारी की फिक्र में प्रायः जहां पुरुष वृद्धों की सुबह-शाम खप जाती है, वहीं वृद्ध महिला एक नौकरानी से अधिक हैसियत नहीं रखती। यदि इस तरह परिवार के वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रुग्णावस्था में बिस्तर पर पड़े कराह रहे हैं, भरण-पोषण को तरस रहे हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में लज्जा एवं शर्म का विषय है। ऐसे शर्म को धोने के लिये ही केरल सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाना एवं सुप्रीम कोर्ट का संवेदनशील होना एक उजाला बना है, जिससे जीवन की संध्या को कष्टपूर्ण होने से निजात मिलने की उम्मीदें जगी है।

करियर की अंधी दौड़ का शिकार युवा पीढ़ी

आमतौर जो बच्चे दसवीं बारहवीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करके करियर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनमें कुछ राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा भी पहुंच जाते हैं। 16-17 साल की कच्ची उम्र में जब उन्हें संसार की कोई खास समझ नहीं होती, जीवन के उतार चढ़ाव का कोई खास अनुभव नहीं होता, उस आयु में वे कोटा पहुंचकर अपना करियर बनाने में जुट जाते हैं। जो बच्चे अपनी इच्छा से ऐसा कर रहे हैं उनके सामने तो कोई समस्या नहीं है लेकिन जिन बच्चों की अनिच्छा के बावजूद उन्हें कोटा की कोचिंग फैक्ट्री में धकेल दिया जाता है, उनमें से हताश निराश कुछ बच्चे अपनी जीवनलीला को ही समाप्त कर देते हैं। बीते एक हफ्ते में फिर से दो बच्चों ने अपने मां बाप से क्षमा मांगते हुए अपनी जान दे दी। दोनों के मरने की एक ही वजह थी, कोचिंग की पढ़ाई के बोझ से दबी मासूम जानों का कहना था कि हमसे यह नहीं हो पायेगा।

भारत में करियर का प्रेशर एक महामारी की तरह फैल रहा है। जीवन जीने के लगभग सभी तरीकों को

16-17 साल की कच्ची उम्र में जब उन्हें संसार की कोई खास समझ नहीं होती, जीवन के उतार चढ़ाव का कोई खास अनुभव नहीं होता, उस आयु में वे कोटा पहुंचकर अपना करियर बनाने में जुट जाते हैं।

अप्रासंगिक घोषित करके सिर्फ कुछ तरीकों को सफलता का मानक घोषित कर दिया गया है। खासकर मध्यवर्ग के सामने आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है अपने बच्चे का अपने से बेहतर करियर बनाना। मिडिल क्लास के इस 'बेहतर करियर' की लिस्ट बड़ी छोटी है। सिविल सर्वेन्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर फाइनेन्सियल सेक्टर जैसे कुछ चुनिंदा क्षेत्र ही हैं जिसे मिडिल क्लास करियर की सफलता मान बैठा है। इसलिए इन क्षेत्रों में अपने बच्चों को घुसाने और किसी तरह पास करवा देने के लिए वह न केवल अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर रहा है बल्कि अपने बच्चों पर भी दिन रात पढ़ाई का दबाव बना रहा है ताकि किसी भी तरह से वो इन्हीं कुछ चुनिंदा सेक्टर में वह अपना करियर बना ले। मिडिल क्लास को लगता है कि ऐसा हो जाने पर या तो उनका बच्चा विदेश चला जाएगा और विदेश नहीं भी गया तो देश में ही इतना पैसा कमा लेगा कि उसकी जिन्दगी सुख चैन से कट जाएगी।

लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वो एक बात नहीं सोच पाते कि किसी के भी साथ उसकी इच्छा या रुचि के विपरीत हम उससे जो कुछ करवाते हैं, हम उस पर गुलामी को थोपते हैं। फिर वह भले ही हमारा अपना बच्चा ही क्यों न हो। अगर उसकी इच्छा पढने की नहीं है तो जबर्दस्ती उसको पढाना भी उसके बाल मन के साथ अपराध करना है। अगर वह किसी खास फील्ड में अपना करियर नहीं बनाना चाहता तो उस ओर उसे धकेलना भी उसके साथ मानसिक प्रताड़ना और क्रिमिनल एक्ट ही समझा जाएगा। अक्सर ऐसा वही मां बाप करते हैं जो अपनी जड़ों से कट चुके हैं। जिन्होंने अपने जीवन की परंपरागत जड़ों को आधुनिकता की अंधी दौड़ में काट दिया है उनके

कोटा में 10 हजार करोड़ का कोचिंग कारोबार है। स्वाभाविक है कोई भी राज्य सरकार इसको बर्बाद नहीं करना चाहेगी। इसलिए पुलिस प्रशासन की ओर से आत्महत्या रोकने के लिए कुछ 'जरूरी इंतजाम' किये जा रहे हैं।

लिए करियर में सफलता जीवन जीने का आधार बन गयी है। करियर में सफल नहीं होंगे तो अच्छा पैसा नहीं कमा पायेंगे और अगर अच्छा पैसा नहीं कमा पाये तो 'सुख चैन' का जीवन नहीं जी पायेंगे। इसके साथ ही समाज में व्यर्थ का प्रदर्शन और दिखावा भी कई बार अपने ही बच्चों के साथ अन्याय का कारण बन जाता है जिसका परिणाम कभी कभार आत्महत्या के रुप में सामने आता है।

भारत में अभी स्कूलों में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। यूरोपीय आदर्शों पर विकसित हुए हमारे स्कूल एक ऐसी फैक्ट्री में तब्दील हो गये हैं जहां जैसा भी कच्चा माल जाए उसे एक ही सांचें में ढालकर एक जैसी प्रतिभा के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। क्लर्क और सेवादार पैदा करनेवाली शिक्षा की इस मैकाले प्रणाली से छुटकारा पाने के बजाय हम लगातार इसमें धंसते ही जा रहे हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी खामी सभी के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा है जिसके कारण बच्चे की स्वाभाविक प्रतिभा विकसित होने की बजाय दमित हो जाती है।

इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था से निकले किसी बच्चे के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वह एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा में घुसकर किसी भी तरह से अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ले। जगह बन गयी तो वह सफल है और अगर जगह नहीं बन पायी तो वह भी अपने आपको असफल मानता है और लोग भी उसे असफल समझते हैं। सबसे पहले तो हमें जीवन की इस संकुचित और दोषपूर्ण मानसिकता से अपने आपको तथा अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। दूसरी बात यह कि लोग किस बात को सफलता मान रहे हैं यह हमारे लिए मानक नहीं होना चाहिए। हमारे लिए जीवन की सफलता वह है जिसमें हम पूर्णता का अनुभव कर सकें।

जीवन की सफलता जीवन की पूर्णता में है। करियर के रूप में हमें भी वही रास्ता चुनना चाहिए जिससे हमारे जीवन में हमें पूर्णता का अनुभव हो। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्णता की इस अनुभूति का नौकरी और करियर एकमात्र रास्ता नहीं है। जीवन में पूर्णता का अनुभव करने के लिए बहुविधा आयाम है। पारिवारिक, सामाजिक या फिर आंतरिक रूप से अपने आपको समृद्ध करके हम जीवन में इस पूर्णता और उस सच्चे सुख चैन को पा सकते हैं जिसकी तलाश करियर बनाने में करते हैं।

लेकिन एक ओर जहां मां बाप पहली कक्षा से बच्चों को पढाई में अव्वल आने का दबाव बनाने लगते हैं वहीं दूसरी ओर थोड़ी समझ आते ही नौजवान कैरियवाद का शिकार बन जाते हैं। करियरवाद की अंधी दौड़ में शामिल होकर वो कुछ भी करने और कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन जीने के दोनों तरीके गलत हैं और ये दोनों ही तरीके किसी को भी सिर्फ अवसाद और हताशा की ओर ले जाएंगे। इसी गलत जीवन दर्शन का परिणाम है कि कभी छोटे छोटे अबोध बच्चे पढाई के बोझ से बचने के लिए घर छोड़कर भाग जाते हैं तो किशोर नौजवान करियर बनाने का दबाव झेलते झेलते फांसी का फंदा चुन लेते हैं। कोटा में 10 हजार करोड़ का कोचिंग कारोबार है। स्वाभाविक है कोई भी राज्य सरकार इसको बर्बाद नहीं करना चाहेगी। इसलिए पुलिस प्रशासन की ओर से आत्महत्या रोकने के लिए कुछ 'जरूरी इंतजाम' किये जा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा जो उपाय किये जा रहे हैं वो सरकारी खानापूर्ति और दिखावटी हैं। समस्या वहां है ही नहीं जहां इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। समस्या परवरिश और करियर बनाने के पारिवारिक दबाव में है। घर परिवार और दोस्तों से दूर ये हताश निराश बच्चे एकांत पाते ही जीवनलीला समाप्त कर लेते हैं। 2016 से अब तक का आंकड़ा देखें तो कोटा में औसत हर साल 18-20 बच्चे आत्महत्या करते हैं। पिछले साल तो यह आंकड़ा 27 तक पहुंच गया है। फिर भी लोग हैं कि कैरियवाद की अंधी दौड़ में फंसकर अपने बच्चों को खुद ही मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, बिना यह समझे कि उनके बच्चे की वास्तविक क्षमता या इच्छा क्या है।

कोटा ही नहीं पूरे देश में बच्चों और किशोर नौजवानों को इससे बचाना है तो उन पर पढाई और करियर का दबाव डालने से बचना होगा। अपने बच्चों को उनकी स्वाभाविक रूचि का करियर बनाने दें। अपनी रुचि के क्षेत्र में जाएंगे तो नाम और पैसा तो बनायेंगे ही, लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि सच्चे सुख चैन से अपना जीवन बिताएंगे।

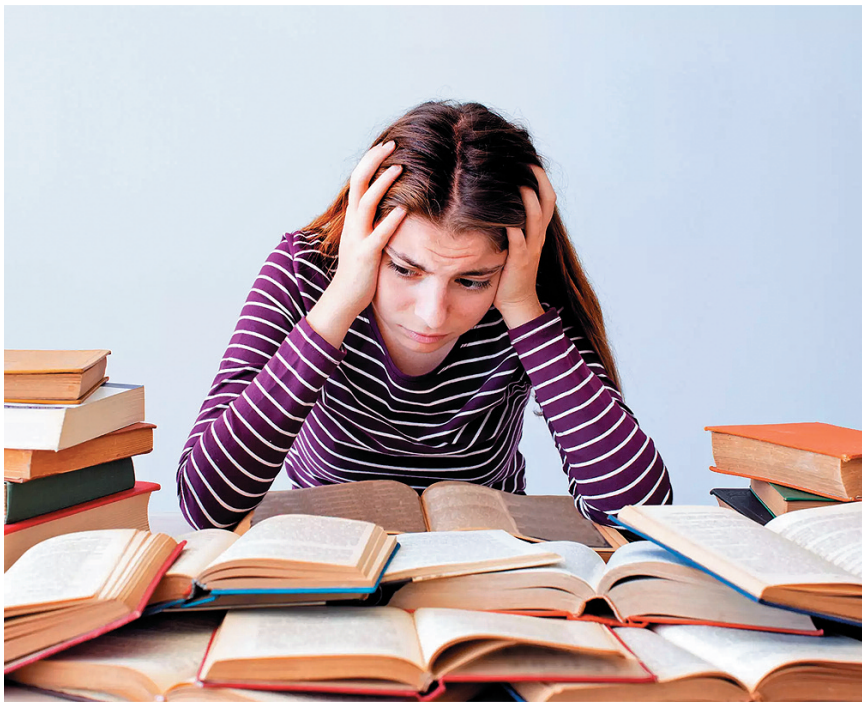

कुल्लू की पार्वती घाटी

गर्मी में लें रोमांचक यात्रा का मजा

अरुण मिश्रा

पार्वती घाटी गर्मी में घूमने जाने के लिए आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यहां के. कलगा-बुनबुनी-खीरगंगा ट्रेक पर दुर्गम पथ पार करने के साथ सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देकर आपका मन प्रफुल्लता से भर जाएगा।

गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का मन बना रहे हैं, तो इसमें हम आपको हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक वादियों में जाने की सलाह देगें। वहां आपको रोमांचक पर्यटन के साथ प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य के दर्शन करने अभिभूत हो जाएंगे। साथ ही खुद को प्रकृति के बहुत नजदीक पाकर खुद में तन-मन से बहुत बदलाव भी महसूस करेंगे।

दरअसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी गर्मी में घूमने जाने के लिए आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यहां के. कलगा-बुनबुनी-खीरगंगा ट्रेक पर दुर्गम पथ पार करने के साथ सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देकर आपका मन प्रफुल्लता से भर जाएगा। पार्वती नदी के पानी के कल-कल की कर्णप्रिय ध्वनि और बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच 28 किलोमीटर लंबा सफर यहां आने वाले पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय दिन बन जाते हैं। इस घाटी सुरम्य वातावरण में आत्मिक शांति का अनुभव होने के साथ आपको स्वयं की सोच में भी बदलाव महसूस होगा। इसके साथ ही आप

मणिकर्ण घाटी का विहंगम दृश्य देखकर असीम खुशी का अनुभव करेंगे। यह रोमांचक ट्रेक पार्वती घाटी में पुलगा डैम के ऊपरी तरफ स्थित कलगा गांव से शुरू होता है। पुलगा डैम तक वाहन से पहुंचा जा सकता है। ट्रेक आरंभ होने के बाद पहला पड़ाव 12 किमी दूर स्थित बुनधुनी है। यहां पहाड़ की चोटी से मणिकर्ण घाटी का विहंगम दृश्य 6 तीन दिन का कलगा-पुनदुनी- खीरगंगा बेहतरीन ट्रेक है। बफीर्ले पहाड़ इस यात्रा में अलग ही रोमांच देते हैं। इस स्थान से सूर्यास्त देखने ता अपना अलग ही अनुभव होता है। यह मनोहारी दृश्य आपको काफी रोमांचक कर देगा।

जंगल के बीच की यात्रा लेंगे लुफ्त

एक दिन बुनलुनी में बिताने केबाद आप अगले दिन खीरगंगा के लिए ट्रेकिंग शुरू कर सकते हैं। करीब 16 किमी की यात्रा में पहाड़ों से गुजरते हुए देवदार के जंगल के बीच आपकों उन वादियां के रोमांचक दृश्यों के साथ प्रकृति से एकाकार होने की अनुभूति होगी। खीरगंगा में रात्रि ठहराव के लिए होटल और हट बनीं हैं। यहां से 18 किमी का सफर तय कर तोष व बरशैणी होते हुए भी आप पुलगा डैम वापस पहुंच सकते हैं।

पानी के झरने, गुरुद्वारा और देवस्थान

खीरगंगा गर्म पानी के झरनों के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है। पर्यटक यहां तोष के रास्ते से भी पहुंचते हैं। रास्ते में मणिकणं गुरुद्वारा और कसौल भी घूमने के लिए अच्छे स्थान हैं। पार्वती घाटी में लुदरनाग से टुंडाभुज-मानतलाई और पिन घाटी होते हुए लाहुल स्पीति का ट्रेक भी है। ये जंगल और ग्लेशियरों का रास्ता है। इसके अलावा भनकड़ जंगल ट्रेक और काफी ऊंचाई पर स्थित सर्व पास यहीं हैं। ये देवी-देवताओं के स्थान हैं और यहां झरने भी हैं। पुलगा गांव से बंडल मार्ग जंगल का ट्रेक भी है। ट्रेकिंग करने का मन न हो तो आप मणिकर्ण से बरशैणी होते हुए खीरगंगा जा सकते हैं। इसके अलावा पुलगा और कलगा मैं भी रुककर मनोरम दृश्यों का सुख पा सकते हैं। यहां होमस्टे और टेंट में रहने की व्यवस्था भी है।

कुल्लू तक कैसे जाएं?

कुल्लू जिले के भुंतर तक सड़क मार्ग के साथ-साथ हवाई मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। भुंतर हवाई अड्डा के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ से उड़ानें हैं। यहां से 25 किमी दूर मणिकर्ण के लिए निजी वाहन या बस से पहुंच सकते हैं। मणिकर्ण से 10 किलोमीटर दूर कलगा गांव है। सड़क मार्ग से चंडीगढ़ से भुंतर की दूरी 203 किमी है। बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है।

ट्रेकिंग के दौरान इन चीजों को साथ रखना जरुरी

ट्रेकिंग के दौरान अपने साथ रेडी भोजन सामग्री ले जा सकते हैं। यहां का तापमान कम रहने के कारण गर्म कपड़े के साथ वर्षा से बचने के लिए रेन सूट, टेंट, लांग बूट और टार्च भी लेकर जाना चाहिए। जंगली जानवरों से सुरक्षा के उपाय भी करने की सलाह पर्यटकों को दी जाती है। ट्रेकिंग के लिए आप अपने साथ गाइड अवश्य साथ रखें। इससे आप स्थानीय महत्व के स्थानों के बारे में जानने के साथ-साथ सुरक्षित पर्यटन का मजा भी ले सकेंगे।

अगर आप भी हैं चाय पीने के शौकीन तो हो जाइए सावधान !

चाय एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है, जिसे दुनिया भर में लोग अपनी सुबह और शाम की शुरूआत के रूप में पसंद करते हैं। लेकिन, चाय पीने की मात्रा आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। तो सवाल यह उठता है कि एक दिन में कितने कप चाय पी सकते हैं ?

डॉ. निमित त्यागी

चाय एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है, जिसे दुनिया भर में लोग अपनी सुबह और शाम की शुरूआत के रूप में पसंद करते हैं। लेकिन, चाय पीने की मात्रा आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। तो सवाल यह उठता है कि एक दिन में कितने कप चाय पी सकते हैं ? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से..

चाय में क्या होता है?

चाय में कैफीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और विभिन्न विटामिन होते हैं। कैफीन शरीर को ताजगी देने के लिए मदद करता है, लेकिन इसकी अधिकता से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

एक दिन में कितनी चाय सुरक्षित है?

आम तौर पर, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2-3 कप चाय रोजाना पीना ठीक रहता है। इस मात्रा में चाय पीने से आप कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स के फायदों का लाभ उठा सकते हैं बिना किसी नुकसान के।

कैफीन का प्रभावः

चाय में कैफीन की मात्रा कॉफी की तुलना में कम होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चाय पीने से यह कैफीन शरीर में अधिक हो सकता है। ज्यादा कैफीन से नींद की समस्या, दिल की धड़कन बढ़ना, और पेट में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

स्वास्थ्य के लिए फायदे

एंटीऑक्सीडेंट्सः चाय में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं।

हृदय स्वास्थ्यः कुछ शोधों के अनुसार, चाय पीने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।

मानसिक ताजगीः चाय पीने से ताजगी मिलती है और मानसिक रूप से सजग रहते हैं।

चाय की अधिकता से नुकसानः

पेट की समस्याः ज्यादा चाय पीने से पेट में गैस, एसिडिटी या दर्द हो सकता है।

नींद में समस्याः कैफीन की अधिकता से रात में नींद नहीं आ सकती है।

हड्डियों पर असरः ज्यादा चाय पीने से कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे हड्डियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

कैसे कम करें चाय की मात्रा?

अगर आप ज्यादा चाय पीने की आदत डाल चुके हैं, तो धीरे-धीरे अपनी चाय की मात्रा कम करें। आप हर्बल चाय जैसे हिबिस्कस या ग्रीन टी का भी विकल्प चुन सकते हैं, जो कैफीन में कम होते हैं। एक दिन में 2 -3 कप चाय पीना आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन ज्यादा चाय पीने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान रखें कि चाय पीने की आदत को संतुलित मात्रा में रखें और शरीर की जरूरतों के अनुसार पीने का ध्यान रखें।

हार्ट अटैक: आने के पहले दिखने लगते है ये 5 लक्षण, इन जगहों पर होता है दर्द

हार्ट अटैक कभी भी किसी को अचानक से नहीं आता है। इसके लक्षण पहले से ही दिखने लगते है। हमारे देश में पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे है। अगर हमें हार्ट अटैक के बारे में या उसके लक्षण पहले.

हार्ट अटैक कभी भी किसी को अचानक से नहीं आता है। इसके लक्षण पहले से ही दिखने लगते है। हमारे देश में पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे है। अगर हमें हार्ट अटैक के बारे में या उसके लक्षण पहले से सही समय पर पता हो जाए तो हम इसका इलाज करा सकते है। यदि इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। हार्ट अटैक से पहले शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द महसूस होता है। आइए जानते हैं हार्ट अटैक आने से पहले शरीर के किन हिस्सों में दर्द हो सकता है...

बाएं हाथ में दर्द

आपको बता दें कि हार्ट अटैक से पहले बाएं हाथ, कंधे या बांह में दर्द महसूस हो सकता है। कभी-कभी यह दर्द गर्दन, जबड़े या पीठ तक भी फैल सकता है। यह लक्षण पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक आम पाया जाता है। अगर इस तरह के संकेत दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

गर्दन और जबड़ों में दर्द

वहीं अन्य मामलों में देखा जाए तो हार्ट अटैक से पहले गर्दन और जबड़ों में दर्द या दबाव महसूस होता है। यह लक्षण विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों में अधिक दिखाई देता है। गर्दन के पास सामान्य खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है, जिसे लोग हल्का दर्द समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं।

पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द

पीठ के ऊपरी हिस्से में अचानक जलन या चुभन जैसा दर्द हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। यह दर्द आमतौर पर महिलाओं में अधिक देखा जाता है। अगर ऐसा दर्द महसूस हो तो इसे हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

सीने में दर्द या जकड़न

इसके साथ ही हार्ट अटैक से पहले सीने में दर्द और जकड़न महसूस होना सबसे आम लक्षण है। यह दर्द हल्का या तीव्र हो सकता है, और मरीज को सीने के बीचों-बीच भारीपन, जलन, दबाव या कसाव जैसा महसूस हो सकता है। यह संकेत बताता है कि दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है।

पेट में दर्द और गैस जैसी उलझन

कुछ लोगों को हार्ट अटैक आने से पहले पेट में भारीपन, जलन, उल्टी जैसा मन, या गैस जैसी समस्या महसूस होती है। लोग इसे एसिडिटी या पेट की समस्याओं का सामान्य लक्षण समझकर अनदेखा कर सकते हैं। अगर पेट में असामान्य दर्द महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें।

हार्ट अटैक से पहले शरीर में इन लक्षणों का दिखाई देना गंभीर संकेत हो सकता है। इसलिए यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। समय रहते इलाज कराने से हार्ट अटैक की गंभीरता को कम किया जा सकता है और जीवन बचाने के अवसर बढ़ सकते हैं।

बढ़ती गर्मी एवं हीट वेव से जुडे.जीवन-संकट

संजय बैंसला

भारत में इस समय गर्मी एवं हीट वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, खासकर उत्तर भारत के अनेक राज्यों विशेषतः गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में अप्रैल के प्रारंभ में ही बढ़ती गर्मी एवं हीट वेव लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी, कई शहरों में पारा 44-45 डिग्री तक चढ़ गया है। राजस्थान के बाडमेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो चिन्ताजनक होने के साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सबब है। लगातार बढ़ती गर्मी के आंकड़े एक बार फिर जलवायु परिवर्तन के परिणामों और इसकी वजह से खड़े हुए संकट को ही दर्शा रहे हैं। अधिक तापमान पानी की गंभीर कमी का कारण बन सकता है, कृषि को प्रभावित कर सकता है और विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम का कारण बन सकता है। भीषण गर्मी एवं लू का प्रकोप लोगों की सेहत, कार्य-क्षमता और उत्पादकता पर गंभीर खतरा है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक, देश का करीब 75 फीसदी कार्यबल कृषि और निर्माण क्षेत्र में गर्मी का सीधे सामना करने वाले श्रम पर निर्भर करता है। इसके मुताबिक साल 2030 तक गर्मी के प्रकोप से जुड़ी उत्पादकता में गिरावट की वजह से दुनिया भर में कुल होने वाली नौकरियों के नुकसान में अकेले भारत का योगदान करीब 43 फीसदी तक हो सकता है।

इस बार बढ़ती गर्मी के पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ देने की चेतावनी दी जा रही हैं जो हमारे लिए चौंकाने से ज्यादा गंभीर चिंता की बात है। गुजरात एवं राजस्थन के अनेक स्थानों पर अभी से गर्मी इतनी तेज है कि कुछ ही दिनों में धरती तवे की तरह तपने लगेगी। पानी की कमी, बिजली कटौती और गर्म लू के कारण बीमारी के हालात गंभीर हो सकते हैं। इतनी तेज गर्मी में पेयजल की उपलब्धता, बिजली की आपूर्ति व ट्रिपिंग की समस्या से निजात पाना मुश्किल होगा। सवाल यह है कि इस भीषण लू या यों कहें कि हीटवेव के लिए बहुत कुछ हम, हमारी सुविधावादी जीवनशैली और हमारा विकास का नजरिया भी जिम्मेदार है। आज शहरीकरण और विकास के नाम पर प्रकृति को विकृत करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पेड़ों की खासतौर से छायादार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं गांवों में हो या शहरों में आंख मींचकर कंक्रिट के जंगल खड़े करने की होड़ के दुष्परिणाम से ही गर्मी कहर बरपाती है और प्रकृति एवं पर्यावरण की विकरालता के रूप में सामने आती हैं। जल संग्रहण के परंपरागत स्त्रोतों को नष्ट करने में भी हमने कोई गुरेज नहीं किया। अब विकास एवं सुविधाओं और प्रकृति के बीच सामंजस्य की ओर ध्यान देना होगा, अन्यथा आने वाले साल और अधिक चुनौती भरे होंगे। कंक्रिट के जंगलों से लेकर हमारे दैनिक उपयोग के अधिकांश साधन एवं विकास की भ्रामक सोच तापमान को बढ़ाने वाले ही हैं।

इस बार बढ़ती गर्मी के पूराने सारे रेकॉर्ड तोड़ देने की चेतावनी दी जा रही हैं जो हमारे लिए चौंकाने से ज्यादा गंभीर चिंता की बात है। गुजरात एवं राजस्थन के अनेक स्थानों पर अभी से गर्मी इतनी तेज है कि कुछ ही दिनों में धरती तवे की तरह तपने लगेगी।

विडंबना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की दस्तक देने के बावजूद विकसित व संपन्न देश पर्यावरण संतुलन के प्रयास करने तथा आर्थिक सहयोग देने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम की मार से कोई विकसित व संपन्न देश बचा हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के क्रूर दोहन से औद्योगिक लक्ष्य पूरे करने वाले ये देश अब विकासशील देशों को नसीहत दे रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ता तापमान उन लोगों के लिये बेहद कष्टकारी है, जो पहले ही जीवनशैली से जुड़े रोगों एवं समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता असाध्य रोगों की वजह से चूक रही है। ऐसा ही संकट वृद्धों के लिये भी है, जो बेहतर चिकित्सा सुविधाओं व सामाजिक सुरक्षा के अभाव में जीवनयापन कर रहे हैं। वैसे एक तथ्य यह भी है कि मौसम के चरम पर आने, यानी अब चाहे बाढ़ हो, शीत लहर हो या फिर लू हो, मरने वालों में अधिकांश गरीब व कामगार तबके के लोग ही होते हैं। जिनका जीवन गर्मी में बाहर निकले बिना या काम किये बिना चल नहीं सकता। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि उन्हें मौसम और गरीबी दोनों मारती है।

प्रतिवर्ष धरती का तापमान बढ़ रहा है। आबादी बढ़ रही है, जमीन छोटी पड़ रही है। हर चीज की उपलब्धता कम हो रही है। आक्सीजन की कमी हो रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा तापमान में लगातार असंतुलन सामान्य घटना नहीं है, जिसका दायरा अब वैश्विक हो गया है। भले ही कोई इस विनाशकारी स्थिति को तात्कालिक घटना कहकर खारिज कर दे लेकिन जमीनी सच्चाई यह है की बड़े पैमाने पर ग्लेशियर्स का पिघलना और हीट वेव बहुत बड़े वैश्विक खतरें की आहट है, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कथित विकास की बेहोशी से दुनियां को जागना पड़ेगा।

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 'तीसरा ध्रुव' कहे जानें वाले हिमालय के ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी के शोधकताओं के अनुसार, आज हिमालय से बर्फ के पिघलने की गति 'लिटल आइस एज' के वक्त से औसतन 10 गुना ज्यादा है। लिटल आइस एज का काल 16वीं से 19वीं सदी के बीच का था। इस दौरान बड़े पहाड़ी ग्लेशियर का विस्तार हुआ था। वैज्ञानिकों की मानें, तो हिमालय के ग्लेशियर दूसरे ग्लेशियर के मुकाबले ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। विशेषज्ञों के एक अनुमान के अनुसार अंटार्कटिका के ग्लेशियर के पूरी तरह से पिघलने पर पृथ्वी की

ग्रेविटेशनल पावर शिफ्ट हो जाएगी। इससे पूरी दुनिया में भारी उथल पुथल देखने को मिलेगी। पृथ्वी के सभी महाद्वीप आंशिक रूप से पानी के भीतर समा जाएंगे। भारी मात्रा में जैव-विविधता को हानि पहुंचेगी। पृथ्वी पर रहने वाली हजारों प्रजातियां भी खत्म हो जाएंगी। पृथ्वी पर एक विनाशकारी एवं विकराल स्थिति का उद्भव होगा। इसके साथ ही दुनियां भर में करोड़ों की संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना पड़ेगा।

दुनियाभर में कूलिंग सिस्टम्स यानी एयरकंडीशन की मांग कई गुना बढ़ी है। सुविधावादी जीवनशैली एवं तथाकथित आधुनिकता ने पर्यावरण के असंतुलन को बेतहाशा बढ़ाया है। तापमान में भी साल-दर-साल बढ़ोतरी अनेक संकटों की दस्तक है। जहां तापमान ने नए रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं वहीं, भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। सरकारों को नीतिगत फैसला लेकर बदलते मौसम की चुनौतियों को गंभीरता से लेना होगा। समय रहते बचाव के लिये नीतिगत फैसले नहीं लिए गए तो एक बड़ी आबादी के जीवन पर संकट मंडराएगा। यह संकट तीखी गर्मी से होने वाली बीमारियों व लू से होने वाली मौतें ही नहीं होंगी, बल्कि हमारी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा श्रृंखला भी प्रभावित होगी। हालिया अध्ययन बता रहे हैं कि मौसमी तीव्रता से फसलों की उत्पादकता में भी कमी आई है। दरअसल, मौसम की यह तल्खी केवल भारत ही नहीं ,वैश्विक स्तर पर नजर आ रही है।

सरकारों को मानना होगा कि वैसे तो प्रकृति किसी तरह का भेदभाव नहीं करती मगर सामाजिक असमानता के चलते वंचित समाज इसकी बड़ी कीमत चुकाता है। सरकार रेड अलर्ट व ऑरेंज अलर्ट की सूचना देकर अपने दायित्वों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूल-कालेजों के संचालन, दोपहर की तीखी गर्मी के बीच कामगारों व बाजार के समय के निर्धारण को लेकर देश में एकरूपता का फैसला लेने की जरूरत है। कुछ जगहों पर धारा 144 लागू करना इस संकट का समाधान कदापि नहीं है।

कभी संवेदनशील भारतीय समाज के संपन्न लोग सार्वजनिक स्थलों में प्याऊ की व्यवस्था करते थे। लेकिन आज संकट यह है कि पानी व शीतल पेय के कारोबारी मुनाफे के लिये सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति को बाधित करने की फिराक में रहते हैं। सरकारें भी जल के नाम पर राजनीति करती है। हमारे राजनीतिज्ञ, जिन्हें सिर्फ वोट की प्यास है और वे अपनी इस स्वार्थ की प्यास को पानी से बुझाना चाहते हैं। विभिन्न प्रांतों के बीच का यह विवाद आज हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रहा है, जनजीवन से खिलवाड़ कर रहा है। इस तरह की तुच्छ एवं स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेता क्या गर्मी एवं जल-समस्याओं का समाधान दे पायेंगे?

बॉलीवुड में नेपोटिज्म, यानी भाई-भतीजावाद होना कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों बड़बोली एक्ट्रेस कंगना रनोट और एक्टर फिल्म निर्देशक करण जौहर के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने नेपोटिज्म शब्द को विलेन की तरह भले ही बना दिया था। इस बहस में कई सितारे कटघरे में खड़े किये जाने लगे हैं।

नेपोटिज्म ने बनाया स्टार

नेपोटिज्म का मतलब है, किसी प्रतिष्ठित या धनी परिवारों के बच्चों और रिश्तेदारों को बिना योग्यता और स्किल के भी फिल्मों में अवसर दिलाना। कई कलाकारों की शिकायत रहती है कि स्टार किड्स से ज्यादा काबिलियत होने के बावजूद उन्हें दोयम दर्जे के रोल करने को मजबूर किया जाता है। हालांकि इस दलील की यह काट है कि मनोज कुमार और देवानंद जैसे कितने ही बड़े स्टार अपने बच्चों को फिल्मों में स्थापित नहीं कर पाए, जबकि शाहरुख खान जैसे कलाकार बिना किसी बैकग्राउंड के फिल्मों के बादशाह खान बन जाते हैं।

बहरहाल, एक बात तो तय है कि फिल्मी दुनिया में ऐसे कई सितारे हैं, जिन्हें नेपोटिज्म का सहारा नहीं मिलता तो आज वे स्टार नहीं बन पाते। बेशक कई स्टार किड्स अपनी प्रतिभा और मेहनत के बूते ही फिल्मों में जमे हुए हैं, लेकिन यह तो कहा ही जाएगा कि अगर इनके परिवार की बैकग्राउंड फिल्मी नहीं होती तो उन्हें फिल्मों में प्रवेश इतनी आसानी से नहीं मिल गया होता और देखते ही देखते वे स्टार कलाकारों में शुमार नहीं किये जा रहे होते। आइये, देखते हैं कुछ ऐसे ही स्टार, जो नेपोटिज्म के सहारे ही फिल्में पाने में कामयाब रहे हैं।

आलिया भट्ट

बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट और पूर्व मिस इंडिया सोनी राजदान की बेटी आलिया भट्ट के लिए फिल्मों में आना संभव नहीं होता। एक तो वे महेश भट्ट की बेटी हैं, दूसरे उन्हें करण जौहर जैसे स्टार निर्देशक ने डेब्यू किया था। जब उन्हें पहली फिल्म के लिये साइन किया गया था, तब वे मोटी-थुलथुल थीं और उनका ओवरवेट होना फिल्मों के लिये कतई संभव नहीं था। लेकिन करण जौहर के कहने पर आलिया ने अपना वजन घटाया और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में आकर ऐसा धमाका किया कि आज वे सफलतम हीरोइनों में शुमा की जाती हैं। आलिया ने फिल्म 'उड़ता पंजाब' और 'हाइवे' से खुद को एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है।

अर्जुन कपूर

फेमस हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर तो अपनी टीनएज लाइफ में इतने

श्रद्धा कपूर

बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन और विलेन शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर का भी फिल्मी करियर अपने पिता के सपोर्ट से ही खड़ा हुआ। यूं तो श्रद्धा की खूबसूरती किसी हीरोइन से कम नहीं थी, लेकिन अपनी पहली मूवी 'आशिकी टू' में उनकी एक्टिंग औसत दर्जे की ही थी। खैर, इतने दिनों में श्रद्धा ने ठीकठाक एक्टिंग सीख ली है और अब वे बॉलीवुड की लीड एक्ट्रेस बन चुकी हैं।

ज्यादा मोटे और थुलथुल रहे हैं कि फिल्मों में आना उनके लिए एक सपने से कम नहीं था। फिर भी अपने फादर के बैकअप के चलते उन्हें यशराज बैनर की फिल्म 'इश्क जादे' में लीड हीरो का रोल मिला। हालांकि अपनी डेब्यू मूवी के लिए अर्जुन कपूर ने जबरदस्त मेहनत करके अपना वजन काफी कम किया और बन गए बॉलीवुड के रफ एंड टफ एक्टर। अब तो अर्जुन की कई फिल्में हिट हो चुकी हैं।

वरुण धवन

बॉलीवुड में फैमिली कॉमेडी मूवीज बनाने के लिए मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे वरुण धवन को शुरूआत में एक्टिंग न के बराबर आती थी, लेकिन अपने पिता के सपोर्ट के कारण उन्हें करण जौहर की मूवी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से डेब्यू करने का मौका मिला। पिता द्वारा तमाम मूवीज में पुश करने का नतीजा ये है कि आज वरुण धवन बॉलीवुड के उभरते हुए स्टार हैं।

आथिया शेट्टी

बॉलीवुड के टॉप एक्शन हीरो सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी को मिले पिता के सपोर्ट से पहली फिल्म मिली 2015 में। सलमान खान और सुभाष घई की प्रोड्यूस की गई मूवी 'हीरो' में उन्हें सूरज पंचोली के साथ हीरोइन लिया गया। यह मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। खराब एक्टिंग के बावजूद काफी दिनों बाद फिर से उन्हें अनीस बज्मी की मूवी 'मुबारकां' में अर्जुन और अनिल कपूर के साथ काम करने का मौका मिला।

सोनाक्षी सिन्हा

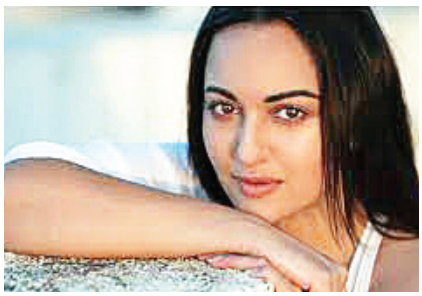

बॉलीवुड फेमस एंग्री यंगमैन एक्टर शत्रुघन सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को अपने पिता के सपोर्ट से दमदार मूवी से ही डेब्यू करने का मौका मिला। सलमान खान की दबंग मूवी से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली सोनाक्षी ने पहली ही फिल्म से कमाल कर दिया। पहली मूवी में ही सोनाक्षी की एक्टिंग काफी अच्छी रही। इसका ही नतीजा है कि उनके पास अच्छी मूवीज की कभी कमी नहीं रही। हालांकि नेपोटिज्म का आशीर्वाद लेकर बॉलीवुड में उतरे उनके भाई को सक्सेस का स्वाद अभी नहीं मिला है।

टाइगर श्रॉफ

बॉलीवुड के फेमस एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ के लिए फिल्मों में आना ही काफी मुश्किल लग रहा था। उन्हें 'गे' कहकर बदनाम किया गया। हालांकि, इस सबके बावजूद टाइगर को 'हीरोपंती' में कृतिसेनन के साथ डेब्यू किया गया। फिल्म में टाइगर ने जबरदस्त स्टंट किये। हालांकि यह फिल्म खास नहीं चल पाई। फिर भी उन्हें फिल्मों में मौके मिलते रहे। बागी, हीरोपंती, फ्लाइट जट और मुन्ना माइकल जैसी कई मूवीज में काम करके टाइगर बॉलीवुड में थोड़ा थोड़ा जमने लगे हैं।

रणवीर कपूर

रणवीर कपूर हिन्दी फिल्मों के सुपर स्टार हैं।

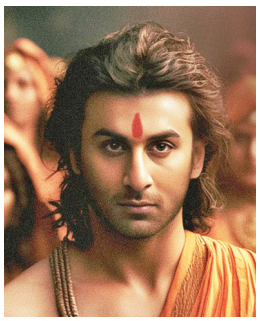

सांवरिया फिल्म से डेब्यू करने के बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा है और वे अपने परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर और पिता ऋषि कपूर की ही राह पर हैं। दरअसल, कपूर परिवार में तकरीबन सभी लड़के फिल्मों में भाग्य आजमाते रहे हैं। हर पीढ़ी में एक-दो सुपर डुपर स्टार रहे हैं। रणवीर कपूर कहते हैं कि दादा-परदादा की फैक्ट्री को यूं ही क्यों छोड़ दिया जाए? दर्शक चाहेंगे तो वे फिल्में करते रहेंगे। नहीं चाहेंगे तो भगवान भी उन्हें फिल्मों में नहीं टिकने दे पाएगा।

सोनम कपूर

पॉपुलर एक्टर अनिल कपूर की बेटी सोनम, हीरोइन बनने की उम्र में काफी ओवरवेट थीं। पापा अनिल कपूर के एफर्ट से सोनम को मिली पहली हिदी फिल्म संजय लीला भंसाली की 'सांवरिया'। जिसमें उनके अपोजिट रणबीर कपूर भी डेब्यू कर रहे थे। यह मूवी भी कुछ खास नहीं चली। हालांकि बॉलीवुड की इस फैशन गर्ल ने हार नहीं मानी। बाद में फिल्म 'नीरजा' में शानदार अभिनय के लिये सोनम को कई अवार्ड मिले और अब वे सफल हीरोइनों में शुमार की जाती हैं।

चेन्नई के खराब प्रदर्शन से धोनी की फिटनेस पर उठ रहे सवाल

चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल की मजबूत टीम माना जाता है जिसने अब तक 5 बार यह खिताब जीता है। देश के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी इस टीम के साथ आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। वह 43 साल के हो चुके हैं पर, अब भी खेल रहे हैं।

आकांशा गर्ग

आईपीएल के 18वें सत्र में अब तक खेले गए मैचों में कई बातें उभर कर आई हैं। पिछले साल की तीन मजबूत टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की हालत इस बार पतली है जबकि गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन काबिलेतारीफ है। वहीं सबसे महंगे बिके विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको बता दें कि पंत को इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा है। पहले बात करते हैं चेन्नई की टीम की। यह टीम अपने घर में तीन मैच हार चुकी है।

इस नाते महेन्द्र सिंह धोनी की फिटनेस पर सवाल उठने लगे हैं। भारत के पूर्व कप्तान धोनी जुलाई में 44 साल के हो जाएंगे। इतनी उम्र के बावजूद वह आईपीएल में खेलना जारी रखे हुए हैं। दो साल पहले उन्होंने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी थी। युवा रुतुराज गायकवाड़ चेन्नई के नए कप्तान बनाए गए। पर, मौजूदा सत्र के बीच चोटिल होने के कारण उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी। फिर से धोनी के कंधों पर नेतृत्व का भार आन पड़ा है। मगर, उनकी कप्तानी में भी चेन्नई को शुक्रवार को कोलकाता से शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। पांच बार की चैम्पियन रही यह टीम अब तक 7 मैचों में से 5 हार चुकी है। शुरूआती एक मैच जीतने के बाद से धोनी के वर्चस्व वाली यह टीम लगातार पराजय का सामना कर रही है। धोनी की वजह से पीली जर्सी वाली चेन्नई टीम के प्रशंसक करोड़ों में हैं लेकिन अब उनमें निराशा का भाव जाग गया है।

भारत के क्रिकेट इतिहास में आईपीएल की लोकप्रियता चरम पर है। हर साल गर्मियों में होने वाले इस टूर्नामेंट में देश की प्रतिष्ठा भले ही दांव पर न हो लेकिन खिलाड़ियों को मालामाल करने के लिए यह काफी है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग देश का एक ब्रांड बन चुका है। स्टेडियम में आने वाली भीड़ अपने चहेते खिलाड़ियों को चौके छक्के लगाते देखना चाहती है। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल की मजबूत टीम माना जाता है जिसने अब तक 5 बार यह खिताब जीता है। देश के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी इस टीम के साथ आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। वह 43 साल के हो चुके हैं पर, अब भी खेल रहे हैं। हर बार लगता है कि यह धोनी का आखिरी साल है लेकिन उनके करोड़ों प्रशंसक उन्हें रिटायर नहीं होने दे रहे। 2025 का आईपीएल उनका आखिरी है या नहीं, यह कोई नहीं बता सकता। पर, उनके निराशाजनक प्रदर्शन से रिटायरमेंट को

लेकर फिर चर्चा छिड़ गई है। बल्लेबाजी के लिए धोनी का काफी नीचे आना भी सवाल खड़े करता है। जब वह सातवें या आठवें नंबर पर आते हैं तब गेंदें कम बचती हैं। ऐसे में जीत दिलाने के लिए उनकी कोशिश बेकार चली जाती है।

सोमवार 14 अप्रैल को लखनऊ में खेला गया मैच चेन्नई ने अवश्य जीत लिया लेकिन अब भी अंक तालिका में धोनी की टीम आखिरी पायदान पर है। सात में से केवल दो मैचों में चेन्नई को जीत मिली है। ऐसे में नहीं लगता कि सीएसके चोटी की चार टीमों में पहुंच पाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने घरेलू मैदान में पांच विकेट से हार गई। मेजबान टीम से ज्यादा यहां पीली जर्सी वाले प्रशंसक अधिक दिख रहे थे। इसकी एकमात्र वजह महेन्द्र सिंह धोनी हैं जिन्हें खेलते देखने के लिए दर्शक बेताब रहते हैं। धोनी कहीं भी खेल रहे हों उन्हें देखने का क्रेज बरकरार रहता है। मगर, देखने की बात यही है कि वह कब तक खेलेंगे? लखनऊ में धोनी ने 26 रन ही बनाए लेकिन उनके बल्ले से निकले 4 चौके और एक छक्के से इकाना स्टेडियम रोमांचित हो गया।

इसी मुकाबले में लखनऊ टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने इस आईपीएल में पहली बार अर्धशतक बनाया। उनकी नाकामी से टीम पर दबाव पड़ रहा था। पंत की विफलता से टीम प्रबंधन चिंतित भी था। कप्तान के असफल होने से टीम के मनोबल पर असर पड़ता है। उन्होंने 63 रनों की पारी खेली। हालांकि, अपनी टीम को जिता नहीं पाए। अभी तक खेले गए मैचों के हिसाब से पंत की टीम चौथे नंबर पर है। उसने 7 में से 4 मैच जीते हैं। वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन इस टीम के दमदार खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं।

दिल्ली की टीम नए कप्तान अक्षर पटेल की अगुवाई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अभी तक ऋषभ पंत दिल्ली के कप्तान थे। दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। उसने 5 में से 4 मैच जीते हैं। गुजरात की टीम अभी चोटी पर है। शुभमन गिल की कप्तानी में इस टीम ने 6 में से 4 मैच जीते हैं। बेंगलुरू की टीम 6 में से 4 मैच जीत कर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। अभी आईपीएल में काफी मैच खेले जाने हैं। टीमें ऊपर नीचे हो सकती हैं। कई नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। पंजाब के प्रियांश ने अपने पहले ही मैच में शतक लगाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

HET

Once You
Buy The

Solar

The Power is Free

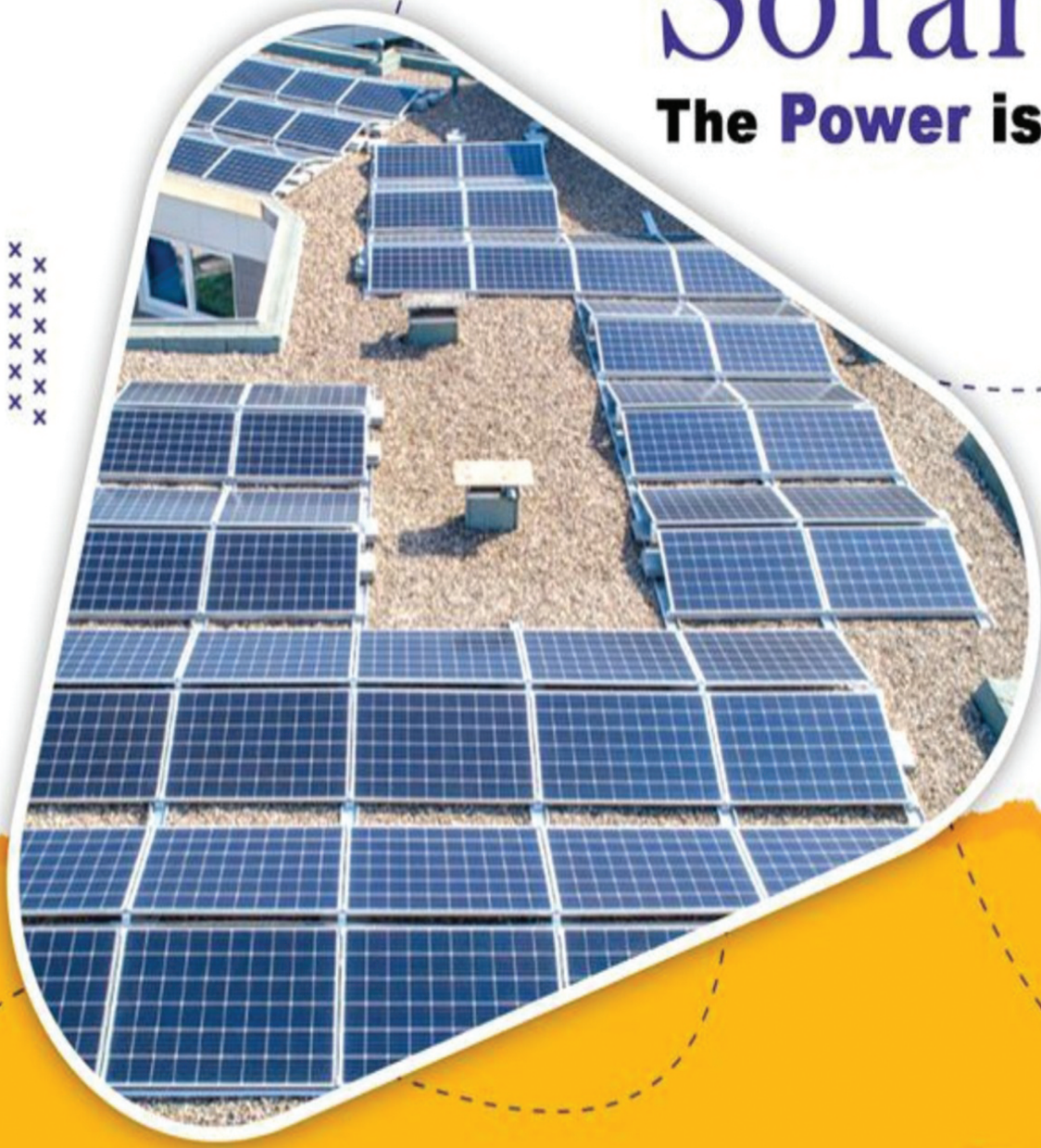

Harshita Electro & Telecom Pvt. Ltd.

SOLAR ON-GRID ROOFTOP SOLUTIONS | OFF GRID SOLAR SYSTEM
HYBRID SOLAR SYSTEM

Office : GF-135, Durga Tower, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad.
Phone : 9891116568, 9891116569, 9899562233

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

उत्तर प्रदेश नं. 1

- देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रथम
- 56 लाख+ परिवारों के लिए पक्के आवास
- पीएम किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में प्रथम
- 1.86 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन का वितरण
- स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि ऋण वितरण में प्रथम
- सर्वाधिक 2.75 करोड़ शौचालयों का निर्माण
- 15 करोड़ नागरिकों को नि:शुल्क राशन का वितरण
- 60 लाख माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना सहायता
- 1.58 करोड़ घरों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन
- 9 करोड़+ लोगों को ₹5 लाख तक का नि:शुल्क उपचार
- 9.57 करोड़ लोगों का जन धन बैंक खाता
- 1 करोड़ परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित